



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022025-260836  
CG-DL-E-11022025-260836

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2025/माघ 17, 1946

No. 37]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2025/MAGHA 17, 1946

## विद्युत मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2025

पंप भंडारण संयंत्रों से भंडारण क्षमता/संग्रहित ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश

सं. 42-26/1/2022-आरसीएम-भाग (3).—

भाग क: कार्यक्षेत्र

### 1. पृष्ठभूमि

1.1. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2023 का उद्देश्य भारत के ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक बनाना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है, क्योंकि देश मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) द्वारा संचालित जीवाश्म से गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी कार्ययोजना के तहत, भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संस्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्वच्छ ईंधन, स्थापित क्षमता मिश्रण का 50% हिस्सा बन जाए। हालाँकि, दिन के समय, मौसम की स्थिति, मौसमी परिवर्तन और भौगोलिक स्थान जैसे कारकों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता इन लक्ष्यों के लिए चुनौतियां पेश करती हैं। सौर, पवन और रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रो जैसे नवीकरणीय स्रोत 24x7 आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (ईएसएस) अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहीत करके और आवश्यकता पड़ने पर इसकी आपूर्ति करके, ग्रिड स्थिरता में सुधार करके, पीक शिफ्टिंग को सक्षम करके और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ाकर इसका समाधान करती हैं।

- 1.2. राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 में, वर्ष 2031-32 तक लगभग 74 गीगावाट/411 गीगावाट आवर ईएसएस की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें पंप भंडारण संयंत्र(पीएसपी) से 27 गीगावाट/175 गीगावाट आवर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) से 47 गीगावाट/236 गीगावाट आवर शामिल हैं।
- 1.3. ईएसएस के उपयोग से पीक डेफिसिट में कमी, पीक टैरिफ में कमी, कार्बन उत्सर्जन में कमी, तथा पारेषण और वितरण पर पूंजीगत व्यय में कमी जैसे लाभ मिलते हैं। ईएसएस ऊर्जा आर्बिट्रेज को भी सक्षम बनाता है, जिससे ग्रिड और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलता है।
- 1.4. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की खरीद और उपयोग के लिए दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) के लिए कोई अलग दिशा-निर्देश नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण, परमिट और मंजूरी, परियोजना समयसीमा और कार्यनिष्पादन मापदंडों जैसे पहलुओं में पीएसपी की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पीएसपी प्रौद्योगिकियों की विशिष्ट बारीकियों का समाधान करने के लिए पीएसपी के लिए अलग दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

## 2. उद्देश्य

इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- 2.1. पम्प भंडारण संयंत्र (पीएसपी) के विकास को बढ़ावा देना।
- 2.2. विभिन्न हितधारकों के बीच उचित जोखिम-साझाकरण के साथ खुली प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित पारदर्शी, निष्पक्ष, मानकीकृत खरीद ढांचा प्रदान करना।

## 3. प्रयोज्यता

- 3.1. ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) से भंडारण क्षमता/ संग्रहित ऊर्जा की खरीद के लिए जारी किए गए हैं।
- 3.2. इन दिशानिर्देशों के प्रावधान निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू होंगे:

- क. विकासकर्ता
- ख. खरीदार (अंतिम खरीदार या मध्यस्थ खरीदार), और

- 3.3. ये दिशानिर्देश खरीदारों द्वारा मौजूदा, निर्माणाधीन या नई पीएसपी परियोजनाओं से भंडारण क्षमता या संग्रहित ऊर्जा की खरीद के लिए लागू हैं।

## 4. परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

- क. "अधिनियम" का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है, जिसमें इसके बाद जारी किए गए संशोधन और स्पष्टीकरण शामिल हैं।
- ख. अनुबंधित भंडारण क्षमता के संबंध में "आपूर्ति तिथि की वास्तविक शुरुआत (एसीएसडी)" का तात्पर्य ऊर्जा के पम्पिंग या उत्पादन के लिए भंडारण क्षमता के प्रारंभ की वास्तविक तिथि के अनुरूप तिथि से होगा।
- ग. किसी कंपनी के संबंध में "सहबद्ध" का अर्थ ऐसी इकाई से होगा जो ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है, उसके द्वारा नियंत्रित होती है, या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में होती है। 'नियंत्रण' शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कंपनी के 50% से अधिक वोटिंग शेयरों का स्वामित्व या बहुमत निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।
- घ. "वार्षिक उपलब्धता" आरएफएस में परिभाषित अनुसार होगी।
- ङ. "समुचित आयोग" का वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
- च. "समुचित सरकार" का वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
- छ. "बोली एजेंसी" से तात्पर्य उस संगठन से होगा जो निविदा दस्तावेज जारी करेगा तथा इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया को अंजाम देगा।

ज. "बोली दस्तावेजों" में आरएफएस दस्तावेज, पीएसपीए और पीएसएसए शामिल होंगे, जिन्हें बोली एजेंसी द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

झ. "समग्र टैरिफ मॉडल" का अर्थ एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें खरीददार एक विनिर्दिष्ट समय के लिए भंडारण-आधारित प्रणाली से विद्युत या ऊर्जा के लिए अनुबंध करता है। इनमें से किसी भी अनुबंध में, रूपांतरण में हानियों सहित भंडारण के लिए ऊर्जा की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जाती है।

ञ. "वितरण बिंदु" का तात्पर्य आरएफएस में विनिर्दिष्ट किसी भी बिंदु से होगा, जहां पीएसपी विद्युत वितरित (सप्लाई) कर रहा है।

ट. "पीपीए की प्रभावी तिथि" का तात्पर्य पीपीए पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा।

ठ. "अंतिम क्रेता" का तात्पर्य मध्यवर्ती क्रेता या पम्प भंडारण संयंत्र विकासकर्ता से भंडारण क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा का अंतिम क्रेता होगा, जैसा भी मामला हो, और इसमें वितरण लाइसेंसधारी भी शामिल होंगे।

ड. "वित्तीय समापन" या "परियोजना वित्तपोषण व्यवस्था" का अर्थ विकासकर्ता द्वारा 100% परियोजना लागत के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था करना होगा, या तो कंपनी द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से निधियों की प्रतिबद्धता के माध्यम से (निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा) और/या किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के माध्यम से ऋण की संस्वीकृति या वित्तपोषण के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता पत्र के माध्यम से निधियों की व्यवस्था करना।

ढ. "अवसंरचना क्षेत्र" का तात्पर्य आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2017 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 13/1/2017-आईएनएफ में अधिसूचित क्षेत्रों से है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

ण. "मध्यस्थ क्रेता" का तात्पर्य एक एजेंसी से है, जिसमें ट्रेडिंग लाइसेंसधारी भी शामिल है जो अंतिम क्रेता(ओं) और विकासकर्ता(ओं) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह एजेंसी विभिन्न विकासकर्ताओं से खरीदी गई भंडारण क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा को एकत्रित करने और तत्पश्चात उसे अंतिम खरीददार(ओं) को बेचने के लिए जिम्मेदार होगी। ऐसे मामलों में जहां ट्रेडिंग लाइसेंसधारी विकासकर्ता(ओं) से भंडारण क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा खरीदता है और इसे एक या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों को बेचता है, ट्रेडिंग लाइसेंसधारी को मध्यस्थ खरीददार माना जाएगा, और वितरण लाइसेंसधारियों को इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए अंतिम खरीददार(रों) माना जाएगा। जब तक मध्यस्थ खरीददार इन दिशानिर्देशों का पालन करता है, तब तक अंतिम खरीददार(रों) को इन दिशानिर्देशों का पालन करने वाला माना जाएगा।

त. "ऑर्डर इंस्ट्रुमेंट पर भुगतान" का तात्पर्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया वचन पत्र (एलओयू) होगा। यह एलओयू, निविदा दस्तावेजों या अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने में डेवलपर की विफलता के मामले में खरीदार (लाभार्थी) को एक विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की गारंटी देगा। एलओयू किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी के समान शर्तों और नियमों पर जारी किया जाएगा।

थ. "खरीददार" का तात्पर्य अंतिम खरीददार या मध्यस्थ खरीददार होगा, जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो।

द. "पंप भंडारण प्रणाली (पीएसपी)" या "परियोजनाओं" का अर्थ एक जल विद्युत संयंत्र होगा, चाहे वह ऑन-स्ट्रीम हो या ऑफ-स्ट्रीम, जो निचली धारा/जलाशय से ऊपरी जलाशय में पानी पंप करके ऊर्जा संग्रहीत करता है और इसे टरबाइन-जनरेटर के माध्यम से वापस छोड़कर विद्युत पैदा करता है।

ध. "पंप भंडारण संयंत्र विकासकर्ता (पीएसपीडी)" या "विकासकर्ता" का अर्थ ऐसी संस्था से है जो पीएसपी का मालिक है या उसका प्रचालन करती है। इन दिशा-निर्देशों के तहत पीएसपी भंडारण क्षमता या विभिन्न स्रोतों से संग्रहीत ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

प. "पंप भंडारण क्रय करार" या "पीएसपीए" या "विद्युत क्रय करार" या "पीपीए" का अर्थ मध्यस्थ खरीददार या अंतिम खरीददार और विकासकर्ता के बीच एक अनुबंध होगा, जिसमें पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) से भंडारण क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा खरीदने की शर्तों का उल्लेख होगा। यह समझौता टोलिंग टैरिफ, समग्र टैरिफ या किसी अन्य लागू मॉडल पर आधारित हो सकता है।

फ. "पंप भंडारण विक्रय करार" या "पीएसएसए" या "विद्युत विक्रय करार" या "पीएसए" का अर्थ मध्यस्थ खरीददार और अंतिम खरीददार के बीच एक समझौता होगा जो टोलिंग टैरिफ या समग्र टैरिफ या किसी अन्य मॉडल के तहत भंडारण क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए होगा। पीएसए (या पीएसएसए) में संबंधित पंप भंडारण क्रय करार (पीएसपीए) या विद्युत क्रय करार (पीपीए) की प्रासंगिक शर्तें शामिल होती हैं, ताकि विकासकर्ता और अंतिम खरीददार के बीच "बैक-टू-बैक" अनुबंध संभव हो सके।

ब. "चयन के लिए अनुरोध" या "आरएफएस" या "निविदा" या "बोली दस्तावेज" का अर्थ बोली एजेंसी द्वारा जारी निविदा दस्तावेज होगा, जिसमें इन दिशानिर्देशों के तहत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भंडारण क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा की खरीद के लिए पंप भंडारण क्रय करार (पीएसपीए) और पंप भंडारण विक्रय करार (पीएसएसए) शामिल हैं।

भ. अनुबंधित भंडारण क्षमता के संबंध में "आपूर्ति की निर्धारित प्रारंभ तिथि (एससीएसडी)" का तात्पर्य आरएफएस में इंगित पर्मिंग या ऊर्जा उत्पादन के लिए भंडारण क्षमता के प्रारंभ की निर्धारित तिथि के अनुरूप तिथि से होगा।

म. "टोलिंग टैरिफ मॉडल" का अर्थ वह मॉडल होगा जिसमें खरीददार भंडारण क्षमता का अनुबंध करता है। भंडारण के लिए ऊर्जा खरीददार द्वारा प्रदान की जाती है और हानियों का हिसाब लगाने के बाद खरीददार द्वारा इसे अलग समय पर लिया जाता है।

य. इन दिशानिर्देशों में "अनुबंध" शब्द का अर्थ पंप भंडारण क्रय अनुबंध या विद्युत क्रय अनुबंध या पंप भंडारण विक्रय अनुबंध या विद्युत विक्रय अनुबंध होगा।

र. इन दिशानिर्देशों में "आपूर्ति" शब्द का तात्पर्य संग्रहित ऊर्जा या अनुबंधित पीएसपी क्षमता की आपूर्ति से होगा।

## 5. दिशानिर्देशों में स्पष्टीकरण और संशोधन

5.1. बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले खरीददार को दिशा-निर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन के लिए समुचित आयोग की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। तथापि, स्पष्टता के उद्देश्य से, यदि खरीददार बोली दस्तावेज और अन्य परियोजना अनुबंध तैयार करते समय विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है जो इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, तो ऐसे विवरण को इन दिशा-निर्देशों से विचलन नहीं माना जाएगा।

5.2. इन दिशानिर्देशों की व्याख्या या कार्यान्वयन में किसी भी अस्पष्टता, कठिनाई या संशोधन की आवश्यकता की स्थिति में, विद्युत मंत्रालय को स्पष्टीकरण प्रदान करने का अधिकार होगा।

## 6. प्रयोज्य कानून और विनियम

6.1. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियां/खरीद, समुचित सरकार और नियामक आयोगों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों, आदेशों, दिशानिर्देशों और विनियमों के अधीन होंगी।

## भाग ख : बोली

### क. बोली की सामान्य शर्तें

#### 1. बोली/आरएफएस दस्तावेजीकरण

1.1. खरीददार को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली दस्तावेज तैयार करने होंगे। इन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों को मानक बोली दस्तावेजों में उपयुक्त रूप से विस्तृत किया जाएगा।

1.2. खरीददार बोलीदाताओं को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए आरएफएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। इन दिशा-निर्देशों की अधिसूचना से पहले शुरू की गई या पहले से चल रही बोलियों के मामले में, संबंधित निविदा या बोली दस्तावेजों में उल्लिखित प्रावधान लागू होंगे।

1.3. बोली एजेंसी निविदा दस्तावेजों में बोलीदाताओं के लिए उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करेगी।

1.4. खरीददार बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट कर सकता है कि परियोजना खरीददार द्वारा निर्दिष्ट साइट पर स्थापित की जानी चाहिए या विकासकर्ता द्वारा चुनी गई साइट पर। यदि खरीददार बोली दस्तावेजों में परियोजना साइट निर्दिष्ट नहीं करता है, तो विकासकर्ता अपनी साइट चुनने के लिए स्वतंत्र है। जहां स्थान/साइट/भूमि खरीददार द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, उसका विवरण बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

1.5. आरएफएस में आवश्यक मंजूरी, परमिट, लाइसेंस, भूमि व्यवस्था आदि के अधिग्रहण के संबंध में प्रत्येक पक्ष की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया जाएगा, जिसमें भूमि अधिग्रहण, कनेक्टिविटी और अन्य परियोजना आवश्यकताओं से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं। आरएफएस में ऐसे लक्ष्यों/आवश्यकताओं का पालन न करने पर दंड और विकासकर्ता द्वारा नियमित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया जाएगा।

## 2. बोली प्रक्रिया

2.1. खरीददार एक चरण, दो भाग (अलग-अलग तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) को अपनाते हुए बोलियां मांगेगा, बोली प्रक्रिया को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-बोली) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

2.2. सबसे पहले तकनीकी बोली खोली जाएगी और केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएँगी जो तकनीकी बोली मूल्यांकन चरण में अर्हता प्राप्त करेंगे। खरीददार बोलीदाताओं के चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी (ई-आरए) आयोजित करने का विकल्प चुन सकता है, जिसका विशेष रूप से बोलियों को आमंत्रित करने वाले नोटिस और बोली दस्तावेज़ में उल्लेख किया जाएगा। एक ऐसा ई-खरीद प्लेटफॉर्म उपयोग किया जाएगा जिसका सफल ट्रैक रिकॉर्ड हो, और जिसमें पर्याप्त सुरक्षा, संरक्षा और गोपनीयता जैसी विशेषताएँ हों।

2.3. खरीददार को व्यापक प्रचार के लिए आरएफएस नोटिस को कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों और/या अपनी वेबसाइट और/या केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर प्रकाशित करना होगा।

2.4. खरीददार संभावित बोलीदाताओं को बोली-पूर्व सम्मेलन का अवसर प्रदान करेगा तथा किसी भी बोलीदाता को निविदा दस्तावेजों की लिखित व्याख्या प्रदान करेगा जिसे अन्य सभी बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी संबंधित पक्ष केवल लिखित पत्राचार पर ही निर्भर रहेंगे। बोली दस्तावेजों के किसी भी स्पष्टीकरण या संशोधन को सूचना के लिए खरीददार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों में किसी भी संशोधन या संशोधन के जारी होने की स्थिति में, बोलीदाताओं को बोलियां प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 7 दिनों की अवधि दी जाएगी।

## 3. खरीद का तरीका

खरीद का तरीका बोली की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

## 4. बोली प्रक्रिया के लिए सांकेतिक समयसीमा

4.1. बोली प्रक्रिया की विभिन्न गतिविधियों के लिए सांकेतिक समय-सीमा बोली की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

4.2. आरएफएस दस्तावेज में विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार खरीददार अलग-अलग समय-सीमाएँ निर्दिष्ट कर सकता है। यदि खरीददार बोली प्रक्रिया में किसी भी घटना के लिए अतिरिक्त समय देता है, तो उस घटना से पहले पूरी की जाने वाली गतिविधियों को प्राप्त करने में देरी के कारण, या किसी अन्य कारण से, समय का ऐसा विस्तार किसी भी तरह से इन दिशानिर्देशों से विचलन के रूप में नहीं माना जाएगा।

## 5. बोली संरचना

5.1. **बोली मानदंड:** संविदा का आवंटन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित होगा। बोली एजेंसी आरएफएस में, बोली की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी बोली मानदंड को निर्दिष्ट कर सकती है, जो आरएफएस में उल्लिखित परियोजना की विशिष्टताओं पर निर्भर करता है।

5.2. टैरिफ को आरएफएस में विनिर्दिष्ट डिलीवरी पॉइंट पर उद्धृत किया जाएगा। कम्पोजिट टैरिफ मॉडल के मामले में, डिलीवरी पॉइंट तक सभी शुल्क और नुकसान विकासकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे, जब तक कि आरएफएस में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो। टोलिंग टैरिफ मॉडल के लिए, डिलीवरी पॉइंट तक शुल्क और नुकसान की जिम्मेदारी आरएफएस में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

5.3. परियोजनाओं की न्यूनतम बोली क्षमता बोली की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

**5.4.** खरीददार एकल बोलीदाता को आवंटित अधिकतम क्षमता को भी परिभाषित कर सकता है, जिसमें पैमाने की अर्थव्यवस्था, भूमि की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा और बाजार विकास जैसे कारकों पर विचार किया जा सकता है। खरीददार विकासकर्ता को मोड-1 में विकसित परियोजनाओं में ज्यादा क्षमता स्थापित करने की अनुमति दे सकता है और ऐसे मामले में खरीददार के पास अतिरिक्त क्षमता/ऊर्जा का संविदा करने से इनकार करने का पहला अधिकार होगा।

#### **5.5. बोली प्रतिक्रियाशीलता**

बोली का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब वह अनुक्रियाशील हो और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो:

- क. बोलीदाता या उसका कोई सहयोगी किसी भी ऋणप्रदाता का इरादतन डिफाल्टर नहीं होना चाहिए;
- ख. बोलीदाता और उसके किसी भी सहयोगी, जिसमें कंसोर्टियम के सदस्य और उसके किसी भी सहयोगी, उनके निदेशक शामिल हैं, को भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा, या बोलीदाता या सदस्यों के अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा जहां वे निगमित हैं या उनके व्यवसाय के मुख्य स्थान के अधिकार क्षेत्र द्वारा, या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, अंतर-अमेरिकी विकास बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक आदि या संयुक्त राष्ट्र या उसकी किसी भी एजेंसी द्वारा बोली प्रस्तुत करने की तिथि पर प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।

#### **5.6. पात्रता एवं योग्यता मानदंड**

क. बोलीदाताओं द्वारा संघ के गठन की अनुमति होगी, जिस स्थिति में संघ एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा जो बोली प्रक्रिया के दौरान सभी पत्राचार के लिए संपर्क बिंदु होगा। खरीददार संघ के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकता है, और आवश्यकताओं को लॉक कर सकता है।

ख. **सामान्य पात्रता मानदंड:** इन दिशानिर्देशों के तहत जारी निविदाओं में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आना चाहिए:

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक कंपनी।
- ii. संबंधित राष्ट्र के कानूनों के तहत एक विदेशी कंपनी।
- iii. सेवी के तहत पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)। "एआईएफ" को सेवी द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
- iv. उपरोक्त संस्थाओं से मिलकर बना एक संघ।

उपर्युक्त श्रेणियां समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, आदेशों और नीति दस्तावेजों के अधीन होंगी।

ग. **तकनीकी पात्रता मानदंड:** भागीदारी बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा परियोजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, खरीददार, बोली की विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट, अतिरिक्त तकनीकी पात्रता मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे मानदंड परियोजना विकासकर्ताओं की संख्या के आकलन के बाद निर्धारित किए जाने चाहिए, जिनसे मानदंडों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि प्रतिस्पर्धा का पर्याप्त स्तर प्राप्त किया जा सके। तकनीकी पात्रता मानदंड को पूरा करने की कट-ऑफ तिथि को सामान्यतः बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि माना जाना चाहिए।

#### **घ. वित्तीय पात्रता मानदंड:**

- i. **नेट-वर्धा/प्रबंधित परिसंपत्तियां (एयूएम) या निवेश योग्य निधि:**

क. क्रेता यह विनिर्दिष्ट करेगा कि बोलीदाता को बोली की विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट निवल-मूल्य आवश्यकता को पूरा करना होगा।

ख. एक बोलीदाता जो सेवी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) है, उसे प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) का संचयी मूल्य प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि आरएफएस में विनिर्दिष्ट है। एआईएफ का निवल मूल्य, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार गणना की जाएगी और एयूएम का

मूल्य, लागू सेबी (एआईएफ) विनियमों के अनुसार गणना की जाएगी और एआईएफ के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

ग. कंसोर्टियम बोलीदाता की निवल संपत्ति की गणना कंसोर्टियम सदस्यों की संयुक्त निवल संपत्ति के साथ-साथ उन सहयोगियों की निवल संपत्ति के रूप में की जाएगी जो इक्विटी फंडिंग का योगदान करने और कार्यनिष्पादन गारंटी (पीजी) प्रदान करने का दायित्व लेते हैं, यदि कंसोर्टियम का कोई भी सदस्य आरएफएस के अनुसार दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

घ. बोलीदाता (एआईएफ को छोड़कर) अपने सहयोगियों की वित्तीय क्षमता के आधार पर अर्हता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, बोलीदाता के मामले में जो बोली लगाने वाले संघ का हिस्सा है, कोई भी सदस्य अपने सहयोगी की वित्तीय क्षमता के आधार पर मानदंडों को पूरा कर सकता है। हालाँकि, इन दोनों मामलों में, यदि बोलीदाता आरएफएस दस्तावेज़ के अनुसार ऐसा करने में विफल रहता है, तो सहयोगियों को आवश्यक इक्विटी फंडिंग और कार्यनिष्पादन गारंटी (पीजी) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा, सहयोगी (एसोसिएट्स) बोली में सूचित सहयोगी की अपनी स्थिति (इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार) को परियोजना की वास्तविक आपूर्ति तिथि (एसीएसडी) तक बनाए रखेंगे।

ii. **लिक्विडिटी:** यह आवश्यक है कि बोलीदाता के पास परियोजना के लिए निधि आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह/आंतरिक संसाधन हों। खरीददार उपयुक्त मापदण्ड, जैसे वार्षिक कारोबार, मूल्यहास, व्याज और कर से पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी), आंतरिक संसाधन सृजन, बोली लगाने की क्षमता आदि निर्धारित कर सकता है।

**5.7** उद्धृत टैरिफ में जीएसटी शामिल नहीं होगा। विकासकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) या किसी अन्य कर वापसी, छूट या लागू कर कानूनों के तहत लाभ उठाकर जीएसटी प्रभाव को कम करने के उपाय करने होंगे। जीएसटी के अंतिम प्रभाव की प्रतिपूर्ति खरीददार द्वारा लाभों के लिए समायोजन करते हुए सहायक दस्तावेजों के उपस्थित करने पर की जाएगी।

## 6. तकनीकी आवश्यकताएं

6.1. खरीददार बोली की विशेष शर्तों के अनुसार बोली दस्तावेजों में तकनीकी आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट करेगा।

6.2. खरीददार, प्रौद्योगिकी जोखिमों को कम करने और समय पर परियोजना कमीशनिंग सुनिश्चित करने के लिए सिद्ध और प्रचालन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इन दिशानिर्देशों द्वारा कवर की गई ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के प्रकारों पर लागू विशेष तकनीकी मानकों को बोली दस्तावेजों में रेखांकित किया जाएगा। इन मानकों को नवीनतम दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और उद्योग मानकों के साथ संरेखित करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

6.3. पीएसपी के तकनीकी मापदण्ड, पीएसपी विशेषता और कार्यनिष्पादन मापदण्ड परिशिष्ट- । में उल्लिखित हैं।

## 7. संविदात्मक गारंटी

7.1. विकासकर्ता, आरएफएस और अनुबंध के अनुसार खरीददार को निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध कराएगा।

### 7.2. बयाना राशि जमा (ईएमडी)

क. खरीददार बोली की विशेष शर्तों के अनुसार बयाना राशि (ईएमडी) की मात्रा विनिर्दिष्ट करेगा।

ख. सभी सफल बोलीदाताओं के लिए ईएमडी कम से कम पीपीए की प्रभावी तिथि तक वैध रहेगी। उसके बाद, सफल बोलीदाताओं के मामले में ईएमडी वापस (रिलीज) कर दी जाएगी और उसकी जगह कार्यनिष्पादन गारंटी (पीजी) लगा दी जाएगी। शेष बोलीदाताओं के लिए, बोली की विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने के बाद ईएमडी वापस(रिलीज) की जाएगी।

ग. इन दिशानिर्देशों में परिभाषित अनुसार ईएमडी जब्त करना या उस पर रोक लगाना आदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर पीपीए निष्पादित करने में विफल रहने की स्थिति में किया जाएगा।

घ. ईएमडी निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी

i. बैंक गारंटी

या

ii. पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्टूमेंट/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग

या

iii. बीमा ज्ञमानत बांड (इंश्योरेंस सिक्यूरिटी बांड) जिसका भुगतान बैंक गारंटी के समान बिना शर्त किया जाएगा

या

iv. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अनुमोदित उपकरण।

7.3. कार्यनिष्पादन गारंटी (पीजी)

क. खरीददार बोली की विशेष शर्तों के अनुसार कार्यनिष्पादन गारंटी (पीजी) तय करेगा।

ख. पीजी को पीपीए पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

i. बैंक गारंटी

या

ii. पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्टूमेंट/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका उपयोग विकासकर्ता द्वारा पीपीए की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में भुगतान के लिए किया जाएगा।

या

iii. बीमा ज्ञमानत बांड (इंश्योरेंस सिक्यूरिटी बांड) जिसका भुगतान बैंक गारंटी के समान बिना शर्त किया जाएगा

या

iv. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अनुमोदित उपकरण।

ग. अन्य उपायों के अतिरिक्त, इस पीजी को पीपीए के अनुसार किसी भी नुकसान/ विकासकर्ता के बकाया को वसूलने के लिए भुनाया जा सकता है। पीपीए के तहत विकासकर्ता के चूक करने पर पीजी को भुनाकर मध्यस्थ क्रेता द्वारा वसूल की गई क्षति/बकाया राशि क्रेता के खाते में जमा कर दी जाएगी।

घ. पीजी को किसी भी परिसमाप्त क्षति को घटाने के बाद, पूर्ण अनुबंधित क्षमता या खरीददार द्वारा स्वीकृत अनुबंधित क्षमता के अंतिम भाग की वास्तविक आपूर्ति प्रारंभ तिथि (एसीएसडी) के 'डी' दिनों के भीतर विकासकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, खरीददार/मध्यस्थ खरीददार इस अवधि को एसीएसडी से अधिकतम 'एम' महीने तक बढ़ा सकता है, जिसे बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा। 'डी' और 'एम' बोली की विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट हैं। अनुबंधित क्षमता के आंशिक कमीशन के मामले में, अनुबंधित क्षमता के आंशिक कमीशन के अनुरूप पीजी को बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी भी परिसमाप्त क्षति की कटौती के बाद जारी किया जाएगा।

ड. पीजी को भुनाने के विकल्प के रूप में, खरीददार/मध्यस्थ खरीददार विकासकर्ता को बिना किसी नकदीकरण के प्रासंगिक पीजी जारी करने के निमित डिमांड ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से अपेक्षित राशि प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

च. यदि विकासकर्ता इन दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एजेंसी द्वारा जारी वैकल्पिक पीजी के साथ इसे बदलने में सक्षम है, तो क्रेता विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को वापस (रिलीज) कर सकता है, ताकि पीपीए के संदर्भ में विकासकर्ता द्वारा चूक होने की स्थिति में भुगतान किया जा सके।

छ. **विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानूनों का अनुपालन:** यदि किसी विदेशी कंपनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो उसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन करना होगा।

#### 8. बोलियों का प्रस्तुतीकरण और मूल्यांकन

- 8.1. बोलीदाताओं को आरएफएस में निर्दिष्ट गैर-वापसीयोग्य प्रोसेसिंग शुल्क और/या सफलता शुल्क जमा करना आवश्यक हो सकता है।
- 8.2. बोलीदाताओं को अलग-अलग तकनीकी और मूल्य बोलियां प्रस्तुत करनी होंगी। बोलीदाताओं को बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में आवश्यक बोली-गारंटी भी प्रस्तुत करनी होगी।
- 8.3. खरीददार बोलियों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन समिति नामक एक समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिसमें वित्तीय मामलोंबोली मूल्यांकन में/ विशेषज्ञता रखने वाला कम से कम एक सदस्य शामिल होगा। मूल्यांकन समिति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चयनित प्रस्ताव का मूल्य उचित है तथा आवश्यकता के अनुरूप है। यदि उद्धृत दरें प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं तो मूल्यांकन समिति को सभी मूल्य बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- 8.4. तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत बोलियां सभी मूल्यांकन मापदंडों पर आरएफएस दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। केवल आरएफएस में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली बोलियों पर ही मूल्य बोलियों के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।
- 8.5. प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, योग्य बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होनी चाहिए। यदि बोली लगाने के तीन प्रयासों के बाद भी योग्य बोलीदाताओं की संख्या दो से कम है, और खरीददार फिर भी बोली प्रक्रिया जारी रखना चाहता है, तो ऐसा समुचित आयोग की सहमति से किया जा सकता है।
- 8.6. यदि बोली की कीमत में बोली की शर्तों से कोई विचलन पाया जाता है तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस स्तर पर बोलीदाताओं से सामान्यतः कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा।
- 8.7. बोली मूल्यांकन, बोली मापदंडों के आरोही क्रम में बोलियों की रैंकिंग के माध्यम से आरएफएस में उल्लिखित मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। बोली एजेंसी परियोजनाओं के पुरस्कार (अवार्ड) के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी (ई-आरए) कर सकती है।
- 8.8. बोली के मूल्यांकन और सफल बोलीदाता(ओं) के चयन की विस्तृत प्रक्रिया आरएफएस में प्रदान की जाएगी।
- 8.9. बोली प्रक्रिया के समापन के बाद, बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति बोलियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगी और उचित रूप से प्रमाणित करेगी कि बोली प्रक्रिया और मूल्यांकन इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप आयोजित किया गया है।

#### ख. बोली की विशेष शर्तें

विशेष शर्तों के खंड, दस्तावेज के संबंधित भाग में सामान्य शर्तों के खंडों के अनुरूप हैं तथा उन्हें उनके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

#### 3. खरीद का माध्यम

खरीद का माध्यम निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

- क. **माध्यम 1 - खरीददार द्वारा पहचाने गए स्थल पर विकसित पीएसपी से खरीद:** खरीददार बोली दस्तावेजों में पूर्व-विनिर्दिष्ट और चिन्हित स्थल पर परियोजना स्थापित करने का विकल्प चुन सकता है। जहां साइट सरकार या किसी सरकारी संस्था की है, तो ऐसी साइट के उपयोग में अंतर-पीड़िगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए, विकास 25 से 40 वर्ष की अवधि के लिए बिल्ड-ऑन-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओओटी)" के आधार पर होगा, जिसे आरएफएस में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। कार्यान्वयन के बीओओटी मोड में, परियोजना को अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा चिन्हित इकाई को आरएफएस में विनिर्दिष्ट पूर्व निर्धारित राशि पर अंतरित किया जाएगा।

खरीददार को बोली के साथ प्रासंगिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जारी करनी होगी।

इसके अलावा, परियोजना को जोखिम से मुक्त करने के लिए खरीददार एक विशेष वाहन बनाएगा (एसपीवी) व्यवहार्यता गतिविधियों को करेगा। इन गतिविधियों में पर्यावरण मंजूरी-जो सभी पूर्व, वन मंजूरी, भूमि अधिप्राप्ति और अन्य सांविधिक मंजूरियों सहित सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना शामिल है। एसपीवी को कंपनी अधिनियम के तहत एक लाख रुपये की न्यूनतम शेयरधारिता के साथ खरीददार इकाई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा। खरीददार द्वारा निगमित एसपीवी को, कंपनी में शेयरधारिता के समूल्य और एसपीवी के प्रचालन में खरीदकर्ता द्वारा किए गए व्यय के बराबर लागत पर, सफल बोलीदाता को अंतरित (ट्रांसफर) किया जाएगा, जिसे आरएफएस में पूर्व-विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

ख. माध्यम 2 - बोलीदाता द्वारा चिन्हित किए गए स्थल पर विकसित पीएसपी या पहले से शुरू पीएसपी या विकासाधीन पीएसपी से खरीदः इस मामले में आपूर्ति, बोलीदाता द्वारा चिन्हित किए गए स्थल पर विकसित पीएसपी से या पहले से शुरू या विकासाधीन पीएसपी से की जाएगी। इस मामले में विकास 15 से 40 वर्षों की अवधि के लिए “बिल्ड-ऑन-ऑपरेट (बीओओ)” आधार पर हो सकता है, जिसे आरएफएस में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। पीएसपी विकासकर्ता संभावित स्थलों की स्वयं पहचान कर सकते हैं, जहाँ पीएसपी का निर्माण किया जा सकता है या पहले से शुरू या विकासाधीन परियोजनाओं से भंडारण की पेशकश कर सकते हैं। पीएसपी विकासकर्ता को परियोजना के निर्माण की शुरुआत से पहले विद्युत अधिनियम की धारा 8 के तहत सहमति, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, भूमि खरीद आदि सहित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करनी होगी। किसी भी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में देरी के मामले में खरीदार जिम्मेदार नहीं होगा। चयनित बोलीदाता(ओं) को पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले अनुमोदित डीपीआर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

#### 4.1. सांकेतिक समयसीमा

अ. माध्यम 1 और माध्यम 2 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए सांकेतिक समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

क्रम सं.	आयोजन	शून्य तिथि से समय (खरीद के माध्यम 1 के लिए)	शून्य तिथि से समय (खरीद के माध्यम 2 के लिए)
1	बोली दस्तावेज जारी करने की तिथि	शून्य तिथि	शून्य तिथि
2	बोली-पूर्व सम्मेलन, बोली स्पष्टीकरण, साइट सहित परियोजना विशिष्ट विवरण साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटा रूम खोलना, यदि खरीददार आदि द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, तथा आरएफएस दस्तावेज़ में संशोधन	**	**
3	बोली प्रस्तुतीकरण	90 दिन	60 दिन
4	तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन	120 दिन	90 दिन
5	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन और ई-आरए का संचालन	150 दिन	120 दिन
6	लेटर ऑफ अवार्ड जारी करना	195 दिन	165 दिन
7	राज्य विद्युत विनियामक आयोग/केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ अपनाने के लिए याचिका दायर करना#	225 दिन	195 दिन
8	क. एसपीवी (माध्यम-1) (यदि लागू हो) के शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर	285 दिन	255 दिन

	और/या		
	ख. पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर (यदि लागू हो)		

\*\* आरएफएस दस्तावेज़ में किसी भी परिवर्तन के मामले में, खरीददार बोलीदाताओं को अतिरिक्त समय प्रदान करेगा।

# आयोग याचिका दायर करने के 60 दिनों के भीतर टैरिफ अपनाएगा।

### 5.1 बोली मापदंड:

- क. भंडारण शुल्क) रु/{मेगावाट/किलोवाट}/{वर्ष/महीना})
- ख. पूर्व-विनिर्दिष्ट वीजीएफ/वार्षिक सहायता के साथ भंडारण शुल्क) रु/{मेगावाट/किलोवाट}/{वर्ष/माह})
- ग. इनपुट पावर और भंडारण की लागत सहित बिजली के लिए कम्पोजिट टैरिफ (रुपये/किलोवाट आवर के आधार पर) इस मामले में इनपुट पावर विकासकर्ता द्वारा व्यवस्थित की जाती है ("कम्पोजिट टैरिफ मॉडल")

#### नोट:

1. यदि खरीद भंडारण प्रभार अर्थात् "टोलिंग टैरिफ मॉडल" पर आधारित है, तो इनपुट पावर की व्यवस्था भंडारण क्षमता के खरीददार द्वारा की जाएगी।
2. क्रेता बोली दस्तावेज में 5.1 (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट बोली मापदंडों के लिए एक बढ़ती हुई टैरिफ संरचना विनिर्दिष्ट कर सकता है।

5.2 **न्यूनतम बोली क्षमता:** इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) से जुड़ी परियोजनाओं के लिए, बोलीदाता द्वारा पेश की जा सकने वाली न्यूनतम बोली क्षमता 50 मेगावाट होनी चाहिए। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) से जुड़ी परियोजनाओं के लिए, अर्थात्, जब खरीददार और पहचान की गई पीएसपी एक ही राज्य में हों, तो न्यूनतम बोली क्षमता कम से कम 10 मेगावाट हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी राज्यों और अन्य आईएनएसटीएस से जुड़ी परियोजनाओं के लिए, भूमि और पारेषण सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, एक छोटी न्यूनतम क्षमता की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसे पहले से ही आरएफएस में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हालाँकि, खरीददार आरएफएस दस्तावेज़ में यहाँ विनिर्दिष्ट सीमाओं से अलग परियोजना का आकार विनिर्दिष्ट कर सकता है।

### 5.3 बोलीदाताओं द्वारा पूरी की जाने वाली योग्यता आवश्यकताएं

- क. तकनीकी पात्रता मानदंड: आवेदकों को पिछले पांच (5) वर्षों के भीतर अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं को विकसित करने का अनुभव प्रदर्शित करना होगा। विशिष्ट विवरण प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफएस) में उल्लिखित किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
  - न्यूनतम समग्र पूंजीगत व्यय: पिछले पांच (5) वर्षों में शुरू की गई सभी योग्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कुल पूंजीगत व्यय आरएफएस में विनिर्दिष्ट सीमा को पूरा करना होगा
  - प्रति परियोजना न्यूनतम पूंजीगत व्यय: प्रत्येक योग्य अवसंरचना परियोजना में आरएफएस में परिभाषित न्यूनतम पूंजीगत व्यय होना चाहिए।
- ख. वित्तीय पात्रता मानदंड:
  - i. नेटवर्श/प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) या निवेश योग्य निधि: जिस वित्तीय वर्ष में बोलियां जारी की जाती हैं, उसके लिए पीएसपी की अनुबंधित क्षमता की अनुमानित पूंजी लागत के कम से कम 20% के बराबर निवल मूल्य।-अनुमानित पूंजीगत लागत बोली एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

#### ख. वित्तीय पात्रता मानदंड:

- i. नेटवर्श/प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) या निवेश योग्य निधि: जिस वित्तीय वर्ष में बोलियां जारी की जाती हैं, उसके लिए पीएसपी की अनुबंधित क्षमता की अनुमानित पूंजी लागत के कम से कम 20% के बराबर निवल मूल्य।-अनुमानित पूंजीगत लागत बोली एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

## 6.1 बोली दस्तावेजों में तकनीकी आवश्यकताएँ

क. पीएसपी के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को परिभाषित करते समय खरीददार निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा:

- i. विद्युत क्षमता मेगावाट में
- ii. ऊर्जा क्षमता मेगावाट घंटे में
- iii. प्रति दिन घंटों में पम्पिंग/उत्पादन अवधि (एक दिन में निरंतर और गैर-निरंतर घंटों की अधिकतम संख्या)
- iv. प्रति दिन/माह/तिमाही/वर्ष/संपूर्ण अनुबंध अवधि में चक्रों में उपयोग, जैसा लागू हो।

ख. खरीददार अपनी आवश्यकता के अनुसार बोली मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त निष्पादन मापदण्ड भी निर्दिष्ट करना चुन सकता है:

- i. उपलब्धता (%)
- ii. उत्पादन और पर्सिंग मोड के बीच स्विचओवर समय और इसके विपरीत।
- iii. चक्र हानि, यदि लागू हो
- iv. अन्य निष्पादन पैरामीटर

निष्पादन मापदण्ड का मूल्यांकन प्रचालन डेटा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण परियोजना या अनुबंधित क्षमता, जैसा लागू हो, पर विचार किया जाएगा।

## 7.2 बयाना राशि जमा (ईएमडी)

क. ईएमडी उस वर्ष के लिए नए पीएसपी के लिए मेगावाट में अनुबंधित क्षमता की अनुमानित पूँजी लागत का 2% (दो प्रतिशत) से कम नहीं होगी जिनमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं या वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऊपरी सीमा के अनुसार, जो भी कम हो।

ख. चयनित बोलीदाताओं के अलावा अन्य के लिए एलओए जारी करने के 15 दिनों के भीतर ईएमडी रिलीज की जाएगी।

## 7.3 निष्पादन गारंटी (पीजी)

क. पीजी उस वर्ष के लिए नए पीएसपी के लिए मेगावाट में अनुबंधित क्षमता की अनुमानित पूँजी लागत का 5% (पांच प्रतिशत) से कम नहीं होगा जिसमें बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, या वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऊपरी सीमा के अनुसार, जो भी कम हो।

ख. समयरेखा 'डी' = साठ (60) दिन, 'एम' = छह (6) महीने

## भाग ग: अनुबंध

### क. अनुबंध की सामान्य शर्तें

#### 1. अनुबंध अवार्ड और समापन

1.1. क्रेता द्वारा सफल बोलीदाता/परियोजना कंपनी या एसपीवी, जैसा भी मामला हो, के साथ पीपीए हस्ताक्षर किया जाएगा।

1.2. मध्यस्थ क्रेता की भागीदारी के मामले में, मध्यस्थ क्रेता विकासकर्ता(ओं) के साथ एक पीपीए और अंतिम क्रेता(ओं) के साथ एक पीएसए हस्ताक्षर करेगा। पीएसए में विकासकर्ता और क्रेता के बीच संग्रहीत ऊर्जा/भंडारण क्षमता के बैक-टू-बैक अनुबंध को सक्षम करने के लिए पीपीए के प्रासंगिक प्रावधान शामिल होंगे। पीपीए(ओं) पर अधिमानतः पीएसए(ओं) पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। मध्यस्थ क्रेता संचय क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा की खरीद और बिक्री के लिए क्रेता से कम्पोजिट टैरिफ मॉडल के लिए डिस्चार्ज की गई ऊर्जा की प्रति यूनिट 7 पैसे या उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट दर पर ट्रेडिंग मार्जिन और टोलिंग टैरिफ मॉडल के लिए क्षमता शुल्क का 1% (रुपये/मेगावाट/माह) या उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर ट्रेडिंग मार्जिन लेने का हकदार होगा।

- 1.3. कुछ राज्यों में वितरण लाइसेंसधारियों के लिए विद्युत क्रय एक होलिंडंग कंपनी या सरकारी एजेंसी के माध्यम से केंद्रीकृत है। ऐसी कंपनियों/एजेंसियों को इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के लिए खरीदार माना जाएगा न कि मध्यस्थ खरीदार।
- 1.4. एलओए जारी करने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि से अधिक या बोली एजेंसी और सफल बोलीदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत किसी अन्य विस्तारित तिथि से अधिक 12 महीने तक पीपीए पर हस्ताक्षर करने में देरी के मामले में, अवार्ड की गई क्षमता रद्द हो जाएगी। कुछ मामलों में, उपरोक्त समय सीमा के बाद, यदि पीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र संचयी क्षमता निविदा के तहत प्रदान की गई संचयी क्षमता से कम है, तो बोली एजेंसी द्वारा तय की जाने वाली आगे की कार्रवाई बोली दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 1.5. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, खरीदार पीपीए के निष्पादन के बाद, सफल बोलीदाता(ओं) के नाम और उनके द्वारा उद्धृत टैरिफ/शुल्क को घटकों में विभाजित करने के साथ-साथ, यदि कोई हो, सार्वजनिक रूप से प्रकट करेगा। कम से कम तीस (30) दिनों के लिए खरीदार की वेबसाइट पर अपेक्षित विवरण पोस्ट करके सार्वजनिक प्रकटीकरण किया जाएगा।
- 1.6. क्रेता या मध्यस्थ क्रेता एलओए जारी होने के तीस (30) दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत टैरिफ अपनाने के लिए समुचित आयोग से संपर्क करेगा।
- 1.7. टैरिफ को उपयुक्त आयोग द्वारा आवेदन की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर अपनाया जाएगा। यदि समुचित आयोग आवेदन की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो खरीदार विकासकर्ता को आपूर्ति की अनुसूचित प्रारंभ तिथि (एससीएसडी) और वित्तीय समापन (एफसी) तिथि में समय का विस्तार अपनाया जाएगा। यह विस्तार आवेदन की तिथि से साठ (60) दिनों के बाद टैरिफ को अपनाने में समुचित आयोग द्वारा लिए गए समय के अनुरूप होना चाहिए।
- 1.8. पीपीए में मानक प्रावधान शामिल होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो कि जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हों, पीएसए में प्रतिविवित होंगे।

## 2. अवधि

पीपीए की अवधि खरीदार द्वारा संयंत्र के इच्छित उपयोग के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और यह आरएफएस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा। पीपीए अवधि की समाप्ति के बाद, विकासकर्ता परियोजना का संचालन जारी रखने के लिए स्वतंत्र होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब परियोजना स्थल खरीदार द्वारा नामित किया जाता है, तो भूमि व्यवस्था के लिए खरीदार की जिम्मेदारी पीपीए अवधि तक सीमित होगी।

## 3 निष्पादन मापदंड

निष्पादन मापदंड और अन्य शर्तें अनुबंध की विशेष शर्तों में विनिर्दिष्ट होंगी।

## 4. परिसमाप्त क्षति (लिक्विडेटेड डैमेज)

- 4.1 बोली दस्तावेजों, पीपीए या पीएसए में निर्दिष्ट निष्पादन मापदंडों को पूरा करने में कमी के कारण परिसमाप्त क्षति, खरीदार(ओं) /मध्यस्थ खरीदारके लिए संभावित हानि के वास्तविक और उचित अनुमान के अनुसार होना चाहिए।
- 4.2 प्रतिबद्ध क्षमता से कम क्षमता की उपलब्धता पर, किसी भी कमी के लिए क्षमता दर या आरएफएस में निर्दिष्ट पूर्व निर्धारित संख्या, के अनुपात में, शुल्क लगेगा।
- 4.3 सहायक सेवा मापदंडों से संबंधित विचलन के लिए पूर्वनिर्धारित परिसमाप्त क्षति, जैसा कि आरएफएस में निर्दिष्ट है, लगाई जाएगी।
- 4.4 अनुबंध की विशेष शर्तों और आरएफएस दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परिसमाप्त क्षति।

## 5. क्रय की शर्तें

5.1 गैर-निष्पादन के लिए जुर्माना आरएफएस में निर्दिष्ट अनुसार होगा। विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों (आरएलडीसी) / राज्य भार प्रेषण केंद्रों (एसएलडीसी) (इंजेक्शनिंग, इंटरवेनिंग और खरीददार एसएलडीसी / आरएलडीसी सहित) पर इसकी समय-सारणी और इसकी पंचिंग विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

5.2 अतिरिक्त शर्तें अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।

## 6. विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम)

अनुसूची से विचलन के लिए डीएसएम (विचलन निपटान तंत्र) प्रचलित विनियमों के अनुसार लागू होगा। परियोजना के अंत में डीएसएम शुल्क विकासकर्ता द्वारा निपटाये (सेटिल) जाएंगे।

## 7. वित्तीय समापन

निम्नलिखित प्रावधान केवल विकासकर्ता द्वारा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं के मामले में लागू होंगे।

क. विकासकर्ता को पीपीए की प्रभावी तिथि से अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वित्तीय समापन (एफसी) प्राप्त करना होगा। हालाँकि, यदि किसी कारण से इस अवधि को संशोधित करने की आवश्यकता है, तो खरीददार के पास ऐसा करने का अधिकार है।

ख. वित्तीय समापन प्राप्त करने में देरी के मामले में, खरीददार/मध्यस्थ खरीददार पीजी को भुनाएगा, जब तक कि देरी सरकार द्वारा भूमि के आवंटन के कारण, सरकार द्वारा की गई देरी (विकासकर्ता के कारण नहीं) या अप्रत्याशित घटना के कारण न हो। खरीददार विकासकर्ता के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए विस्तार पर विचार कर सकता है, जो अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट विस्तार शुल्क के भुगतान के अधीन है। यह विस्तार एससीएसडी को प्रभावित नहीं करेगा। एससीएसडी के भीतर सफल कमीशनिंग के बाद भुगतान किए गए किसी भी विस्तार शुल्क को बिना व्याज के वापस कर दिया जाएगा। कोई भी गैर-वापसी योग्य जुर्माना या विस्तार शुल्क खरीददार को जाएगा।

## 8. पारेषण कनेक्टिविटी

- 8.1. जीएनए विनियमन के तहत आईएसटीएस नेटवर्क के लिए पारेषण कनेक्टिविटी प्राप्त करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी और यह विकासकर्ता की लागत पर होगी।
- 8.2. विकासकर्ता एलओए जारी करने के 'डी' दिनों के भीतर आईएनएसटीएस/आईएसटीएस सबस्टेशन के लिए संयंत्र की कनेक्टिविटी/ओपन एक्सेस की तकनीकी व्यवहार्यता (टेक्निकल फीजिबिलिटी) के लिए सीटीयू/एसटीयू ग्रिड (आवश्यकतानुसार) के लिए कनेक्टिविटी/जीएनए/ओपन एक्सेस के लिए आवेदन करेगा। 'डी' का मूल्य अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट है।
- 8.3. अंतिम खरीददार लागू कानूनों के तहत अंतरा-राज्यीय पारेषण शुल्क और डिलीवरी पॉइंट से परे नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। अंतःराज्य/अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क और डिलीवरी पॉइंट तक के नुकसान विकासकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 8.4. खरीददार को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा को मीटरिंग प्वाइंट या बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट किसी अतिरिक्त बिंदु पर प्राप्त जाएगा। मीटरिंग प्वाइंट इनएसटीएस/आईएसटीएस सबस्टेशन का लो बोल्टेज बस बार होगा, जिस पर एसटीयू/सीटीयू के पारेषण प्रणाली में विद्युत इंजेक्ट की जाती है।
- 8.5. जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, ऊर्जा लेखांकन के लिए मीटरिंग किए जाने वाले इंटरकनेक्शन के बिंदु तक विद्युत का पारेषण विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी और वह खुद अपने खर्च पर करेगा। अतिरिक्त शर्तें अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।

## 9. आपूर्ति की शुरुआत

- 9.1. विकासकर्ता और खरीददार/मध्यस्थ खरीददार के बीच पीपीए में एससीएसडी और क्षमता की मात्रा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

**9.2.** परियोजनाएं आम तौर पर अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवाएं शुरू कर देंगी। हालांकि, अगर किसी कारण से एससीएसडी अवधि को इन दिशानिर्देशों में दिए गए समय से अधिक/कम रखने की आवश्यकता है, तो खरीदार ऐसा कर सकता है।

**9.3. समय से पहले शुरूआत:** विकासकर्ता को एससीएसडी से पहले भी पूर्ण और आंशिक अनुबंधित क्षमता के अनुरूप आपूर्ति शुरू करने की अनुमति होगी। विकासकर्ता को पूर्ण या आंशिक अनुबंधित क्षमता के अग्रिम कमीशन के संबंध में अंतिम खरीदार(ओं) और मध्यस्थ खरीदार दोनों को कम से कम 'डी' दिन (अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट) की अग्रिम सूचना देनी होगी। अंतिम खरीदार(ओं) और मध्यस्थ खरीदार को नोटिस की सेवा की तारीख से 'डी' डेज़ के भीतर ऐसी संग्रहीत ऊर्जा/भंडारण क्षमता का लाभ उठाने के लिए स्वीकृति देनी होगी। यदि अंतिम खरीदार(ओं) और मध्यस्थ खरीदार दोनों निर्धारित अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो विकासकर्ता भंडारण क्षमता या संग्रहीत ऊर्जा को अंतिम खरीदार(ओं) और मध्यस्थ खरीदार द्वारा स्वीकार नहीं की गई सीमा तक विद्युत एक्सचेंजों में या द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से बेच सकता है। यदि अंतिम खरीदार(ओं) और मध्यस्थ खरीदार दोनों अपनी स्वीकृति देते हैं, तो अंतिम खरीदार(ओं) को आपूर्ति का लाभ उठाने में प्राथमिकता दी जाएगी।

**9.4 आपूर्ति का आंशिक प्रारंभ:** अनुबंधित क्षमता के आंशिक प्रारंभ के मामले में, स्वीकृति के लिए न्यूनतम क्षमता अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट की जाएगी। हालांकि, पीपीए के अनुसार, गैर-कमीशन किए गए हिस्से पर दंड लागू हो सकता है। आंशिक या पूर्ण प्रारंभ तिथियों के बावजूद, एससीएसडी अपरिवर्तित रहेगा। पीपीए एससीएसडी से शुरू होकर पूरे कार्यकाल के लिए लागू रहेगा।

**9.5. आपूर्ति का प्रारंभिक और आंशिक प्रारंभ:** प्रारंभिक और आंशिक प्रारंभ के मामले में, अंतिम खरीदार(ओं) और मध्यस्थ खरीदार द्वारा देय टैरिफ़ पीपीए टैरिफ़ के बराबर होगा। प्रारंभिक और आंशिक प्रारंभ के लिए अन्य शर्तें अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट की जाएंगी।

**9.6. एससीएसडी से परे आपूर्ति शुरू करने में देरी के कारण विकासकर्ता पर दंड लगेगा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:**

**क.** एससीएसडी से आपूर्ति शुरू करने में **6 (छह)** महीने तक की देरी के लिए, प्रतिदिन के आधार पर और आपूर्ति शुरू नहीं करने वाली अनुबंधित क्षमता के अनुपात में निष्पादन गारंटी (पीजी) का नकदीकरण।

**ख.** एससीएसडी से आपूर्ति शुरू करने में छह महीने से अधिक की देरी के लिए, अनुबंधित भंडारण क्षमता, एससीएसडी प्लस **6 (छह)** महीने की अवधि के भीतर आपूर्ति शुरू करने वाली परियोजना क्षमता तक कम हो जाएगी। शेष अनुबंधित क्षमता के लिए पीपीए जिससे आपूर्ति शुरू नहीं की है, समाप्त हो जाएगी।

**9.7. कनेक्टिविटी/ग्रिड एक्सेस ऑपरेशनलाइजेशन में देरी के कारण आपूर्ति शुरू करने में देरी**

सीटीयू/एसटीयू द्वारा ग्रिड एक्सेस देने या संचालन में देरी, या एससीएसडी तक आईएसटीएस/आईएनएसटीएस नेटवर्क की विद्युत निकासी और पारेषण अवसंरचना सहित डिलीवरी पॉइंट/इंजेक्शन पॉइंट पर आईएसटीएस/आईएनएसटीएस सबस्टेशन की तैयारी में देरी को विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर माना जाता है, अगर निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

**क.** विकासकर्ता ने कनेक्टिविटी प्रक्रिया के अनुसार सभी आवेदन औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

**ख.** विकासकर्ता ने समुचित आयोग/सीटीयू/एसटीयू द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक प्रक्रिया का पालन किया है।

**ग.** देरी एसटीयू/सीटीयू/पारेषण लाइसेंसधारी के कारण हुई है और विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर है।

ऐसी परियोजनाओं के लिए एससीएसडी को, डिलीवरी पॉइंट और विजली निकासी बुनियादी ढांचे की तैयारी और/या ग्रिड एक्सेस के संचालन के तीस (30) दिन बाद की तारीख में समायोजित किया जाएगा। उपर्युक्त कारकों के कारण आवश्यक विस्तार के बारे में निर्णय खरीदार/मध्यस्थ खरीदार द्वारा किया जाएगा।

**10. ऑफटेक बाधाओं के लिए मुआवजा**

पारेषण अनुपलब्धता और ग्रिड सुरक्षा के कारण ऑफटेक बाधाओं के लिए मुआवजा अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

## 11. भुगतान सुरक्षा तंत्र

11.1. यदि अंतिम खरीददार वितरण लाइसेंसधारी हैं, जहां टैरिफ समुचित आयोग द्वारा निर्धारित या अपनाया जाता है, तो समय-समय पर जारी संशोधनों और स्पष्टीकरणों सहित विद्युत (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार पर्याप्त भुगतान सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

11.2. यदि आपूर्ति विद्युत बाजारों के माध्यम से बिक्री के लिए है, तो राजस्व में कमी/अधिशेष को केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/आदेशों के अनुसार माना जाएगा और केंद्रीय आयोग द्वारा विनियमित किया जाएगा।

## 12. अप्रत्याशित घटना

12.1. पीपीए में उद्योग मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना की परिभाषा, बहिष्करण, प्रयोज्यता और अप्रत्याशित घटना के कारण उपलब्ध राहत के संबंध में प्रावधान शामिल होंगे।

12.2. विकासकर्ता अप्रत्याशित घटना की शुरुआत के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खरीददार को अप्रत्याशित घटना के बारे में सूचित करेगा और खरीददार सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने दावे पर प्रतिक्रिया देगा।

## 13. चूक की घटना और उसके परिणाम

जबकि संबंधित पक्षों की चूक की घटना और उसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों के संबंध में विस्तृत प्रावधान पीपीए/पीएसए में दिए जाएंगे, विकासकर्ता और खरीददार(ओं) मध्यस्थ खरीददार को छोड़कर) की चूक से अनुबंध के तौर पर निपटने के व्यापक सिद्धांत इस प्रकार होंगे।

क. एससीएसडी से परे आपूर्ति शुरू करने में देरी के लिए, विकासकर्ता की चूक की घटना को घटित माना जाएगा और परिणाम इन दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

ख. यदि विकासकर्ता आरएफएस में निर्दिष्ट अवधि के लिए लगातार न्यूनतम निष्पादन आवश्यकता को बनाए रखने में विफल रहता है, तो विकासकर्ता चूक में होगा और पीपीए समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, विकासकर्ता खरीददार को अपनी अनुबंधित क्षमता के लिए टैरिफ के 'एम' महीनों (जैसा कि अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट है) या शेष पीपीए अवधि के बराबर हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. यदि विकासकर्ता पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किसी अधिकार या दायित्व को सौंपता है या नवीकृत करता है, या पीपीए को अस्वीकार करता है, या पीपीए में निर्धारित कोई अन्य कार्य या चूक करता है और पीपीए में दिए गए उपचार अवधि के भीतर पूर्वोक्त में से किसी को ठीक करने में भी असमर्थ है, तो विकासकर्ता खरीददार को उसकी अनुबंधित क्षमता के लिए टैरिफ के 'एम' महीनों (अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट) या शेष पीपीए अवधि जो भी कम हो, के बराबर हर्जाना देगा। खरीददार को किसी अन्य कानूनी मार्ग या उपाय के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निष्पादन गारंटी, यदि कोई हो, को जब्त करके उक्त हर्जाने को वसूलने का अधिकार होगा।

घ. उपर्युक्त अनुसार हर्जाना लगाने के अलावा, विकासकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में, ऋणदाता पीपीए में दिए गए प्रतिस्थापन प्रावधानों के अनुसार और खरीददार की सहमति से प्रतिस्थापन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार होंगे। हालांकि, यदि ऋणदाता निर्धारित अवधि के भीतर चूक करने वाले विकासकर्ता को प्रतिस्थापित करने में असमर्थ हैं, तो खरीददार पीपीए को समाप्त कर सकता है।

ड. यदि खरीददार/मध्यस्थ खरीददार अन्य कारणों से, जैसे कि आरएफएस के अनुसार बकाया राशि का समय पर भुगतान करने में विफलता या पीपीए को अस्वीकार करने सहित, चूक करता है, तो विकासकर्ता अपने विवेक पर पीपीए को समाप्त कर सकता है। चूककर्ता क्रेता को विकासकर्ता को उसकी अनुबंधित क्षमता के लिए 'एम' महीनों (जैसा कि अनुबंध की विशेष शर्तों में निर्दिष्ट है) या शेष पीपीए अवधि के बराबर, जो भी कम हो, क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

च. यदि विकासकर्ता एससीएसडी और एसीएसडी के बीच की अवधि के दौरान खरीददार की अनुबंधित क्षमता के सभी या हिस्से को वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति करने के लिए सहमत होता है, पीपीए में निर्दिष्ट शर्तों पर, इस खंड के तहत देय हानि, अनुबंधित क्षमता के मुकाबले एसी आपूर्ति की सीमा के आधार पर, आनुपातिक

रूप से कम हो जाएगी। यदि परियोजना पूरी नहीं होती है और एसीएसडी एससीएसडी से दिनों के 180 भीतर नहीं होती है, और जब तक कि देरी अप्रत्याशित घटना के कारण या खरीददार के कारण नहीं होती है, तो खरीददार अपने विवेक पर पीपीए को समाप्त कर सकता है।

#### 14 कानून में बदलाव

कानून में बदलाव के प्रावधानों को विद्युत (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 के अनुसार आरएफएस और पीपीए में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कानून में बदलाव ("सीआईएल") शब्द बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से सात (7) दिन पहले परियोजना से संबंधित किसी भी घटना के घटित होने को संदर्भित करेगा।

#### 15. प्रमोटर द्वारा धारित की जाने वाली न्यूनतम चुकता शेयर पूँजी/शेयरधारिता

- 15.1. सफल बोलीदाता, यदि एकल कंपनी है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पीपीए निष्पादित करने वाली एसपीवी/प्रोजेक्ट कंपनी में उसकी शेयरधारिता एसीएसडी से पहले किसी भी समय 51% (इक्यावन प्रतिशत) से कम नहीं होगी। यदि सफल बोलीदाता एक संघ है, तो पीपीए निष्पादित करने वाली एसपीवी/प्रोजेक्ट कंपनी में संघ के सदस्यों की संयुक्त शेयरधारिता एसीएसडी से पहले किसी भी समय 51% से कम नहीं होगी। इसके अलावा, यदि परियोजना को सफल बोलीदाता द्वारा ही निष्पादित किया जाता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली लगाने वाली कंपनी/संघ की नियंत्रक शेयरधारिता एसीएसडी तक अपरिवर्तित रहे। सफल बोलीदाता खरीददार के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले खरीददार को अपनी शेयरधारिता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- 15.2. एसीएसडी के बाद शेयरधारिता में कोई भी परिवर्तन खरीददार को सूचित करके किया जा सकता है।
- 15.3. यदि विकासकर्ता ऋणदाता(ओं) के प्रति चूक करता है, तो ऋणदाता, खरीददार के परामर्श से "प्रमोटर का प्रतिस्थापन" करने के हकदार होंगे।

#### 16 निर्माण और निष्पादन निगरानी

16.1 इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली सभी ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं को परियोजना के प्रदर्शन को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाने होंगे। विकासकर्ता को यह डेटा पीपीए की पूरी अवधि के लिए आरएफएस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट प्राधिकरणों/एजेंसियों को आँनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में, उन्हें अनिवार्य रूप से खरीददार और विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या समुचित सरकार द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी को 24×7 आधार पर विद्युत संयंत्रों की दूरस्थ निगरानी के लिए पोर्टल तक पहुंच प्रदान करनी होगी। परियोजनाओं की जियो-टैगिंग अनिवार्य होगी।

16.2 जब विकासकर्ता द्वारा किसी परियोजना स्थल की पहचान की जाती है, तो विकासकर्ता सभी मंजूरियाँ प्राप्त करने के लिए ज़िम्मेदार होगा और खरीददार ऐसी मंजूरियाँ प्राप्त करने में देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। विकासकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्ति की समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए आरएफएस में निर्धारित समयसीमा के अनुसार विभिन्न तैयारी और कार्यान्वयन गतिविधियाँ पूरी की जाएँ।

#### 17 राज्य नोडल एजेंसियों और अन्य सुविधा प्रदाताओं की भूमिका

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य नोडल एजेंसियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में सुविधा शामिल हो सकती है:

- क. परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय।
- ख. परियोजनाओं के शुरू होने के दौरान सहायता।

#### 18 विवाद समाधान तंत्र

18.1 टैरिफ से संबंधित कोई भी विवाद या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 और धारा 86 के प्रावधानों के तहत निपटाए गए मामलों का समुचित आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अन्य सभी विवादों का समाधान उचित सरकार द्वारा गठित विवाद समाधान समिति द्वारा किया जाएगा और यदि समिति विवाद को हल करने में विफल रहती है, तो इसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के माध्यम से समाधान किया जाएगा।

**18.2** विवाद समाधान समिति कानून के प्रावधानों से परे एक अतिरिक्त मंच होगी और इसका उपयोग संबंधित पक्ष अपनी इच्छानुसार कर सकेगे।

#### ख. संविदा की विशेष स्थितियां

विशेष शर्तों के खंड, दस्तावेज के संबंधित भाग में सामान्य शर्तों के खंडों के अनुरूप हैं तथा उन्हें उनके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

#### 3. कार्य निष्पादन मापदंड

क. बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट परियोजना के कार्य निष्पादन मापदंड जिनमें उपलब्धता, चार्जिंग/डिस्चार्जिंग दर, दक्षता, रैंप दर, साइकलिंग हानियाँ, क्षमता ह्रास, और दैनिक/मासिक चक्र शामिल हो सकते हैं, उन्हें पीपीए में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाएगा। जहाँ उपलब्धता एक प्रदर्शन मानदंड है, वहाँ पीपीए को न्यूनतम स्तर निर्दिष्ट करना चाहिए जिस पर विकासकर्ता को पीएसपी को बनाए रखना चाहिए। पीएसपी के इच्छित उपयोग के आधार पर, विकासकर्ता को मासिक और/या वार्षिक उपलब्धता आवश्यकताओं को पूरा करने या एक दिन पहले उपलब्धता की घोषणा करने की आवश्यकता हो सकती है। खरीददार विशिष्ट घंटे और प्रदर्शन मापदंड निर्दिष्ट कर सकता है, न्यूनतम उपलब्धता मानदंड को निर्दिष्ट घंटों या अधिकतम घंटों तक सीमित कर सकता है, किसी भी कमी की गणना तदनुसार की जाएगी।

ख. जब अनुबंध भंडारण के लिए होता है, तो ऊर्जा को अंतिम खरीददार द्वारा स्वतंत्र रूप से खरीदा जाएगा और प्रदान की गई क्षमता में संग्रहीत किया जाएगा। विकासकर्ता पूर्व निर्धारित कन्वर्जन हानियों के लिए लेखांकन करते हुए संग्रहीत ऊर्जा को वापस कर देगा। अंतिम खरीददार अवार्ड की गई क्षमता के लिए भंडारण शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है, चाहे क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया हो या नहीं।

#### 4.4. कार्य निष्पादन में कमी के लिए अतिरिक्त परिसमाप्त क्षति

विकासकर्ता गारंटीकृत मापदंड (आरएफएस दस्तावेज में निर्दिष्ट) से अधिक ऊर्जा हानि की लागत को, खरीददार द्वारा प्रदान की गई इनपुट ऊर्जा के टैरिफ या आरएफएस में निर्दिष्ट किसी भी संख्या पर, वहन करेगा।

#### 5.2 खरीद की अतिरिक्त शर्तें

क. उपलब्ध क्षमता/ऊर्जा में किसी भी कमी के लिए, पीपीए में परिसमाप्त क्षति के लिए उचित प्रावधान होंगे। इस तरह के जुर्माने की राशि पीपीए की शर्तों के अनुसार, भंडारण क्षमता/ऊर्जा में कमी के लिए पीपीए टैरिफ के डेढ़ गुना के बराबर होगी।

ख. अधिकतम निर्दिष्ट वार्षिक अनुबंधित संग्रहीत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की उपलब्धता के मामले में, विकासकर्ता, खरीददार(ओं) को इनकार करने का पहला अधिकार प्रदान किए बिना इसे किसी अन्य इकाई को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

ग. विकासकर्ता खरीददार(ओं) से एनओसी की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को बिना मांगी क्षमता/ऊर्जा को बेच सकता है।

#### 7. वित्तीय समापन

क. वित्तीय समापन अवधि 12 माह की अवधि में होगी।

ख. विस्तार शुल्क एससीएसडी में प्रति दिन देरी के लिए अनुबंधित क्षमता का प्रति मेगावाट 1,000 रुपये होगा।

#### 8. पारेषण कनेक्टिविटी

**8.2.** कनेक्टिविटी/जीएनए/सीटीयू/एसटीयू ग्रिड तक खुली पहुंच के लिए 'डी' = एलओए जारी होने के साठ (60) दिन के भीतर आवेदन किया जाएगा।

#### 8.5. पारेषण कनेक्टिविटी की अतिरिक्त शर्तें

भंडारण क्षमता की क्रय के मामले में, मीटरिंग प्वाइंट पर अनुबंधित पीएसपी क्षमता को चार्जिंग ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ-साथ मीटरिंग प्वाइंट से परे अनुबंधित पीएसपी क्षमता से डिस्चार्ज ऊर्जा के संचरण की जिम्मेदारी अंतिम खरीददार की होगी।

## 9. आपूर्ति की शुरुआत

### 9.2 भंडारण की शुरुआत

(i) परियोजनाएं आम तौर पर निम्नलिखित अवधि के भीतर शुरू होंगी:

क्रसं.	खरीद मोड प्रकार	पीएसपी का प्रकार	पीपीए की प्रभावी तिथि के बाद एससीएसडी (महीने)
1.	मोड 1	आफ़ रिवर	48 माह
		आनें रिवर	66 माह
2.	मोड 2	-	खरीददार की आवश्यकता के अनुसार

### 9.3 शीघ्र प्रारंभा

सूचना अवधि कम से कम 'डी' = पंद्रह (15) दिन होगी

### 9.4 कमीशनिंग के लिए न्यूनतम आंशिक क्षमता

आंशिक कमीशनिंग के लिए पहले भाग की न्यूनतम क्षमता परियोजना क्षमता का 50% या 50 मेगावाट, जो भी कम हो, होगी।

### 9.5 शीघ्र और आंशिक कमीशनिंग

क्षमता क्रय अनुबंधों में, यदि परियोजना आंशिक रूप से चालू है, तो पीपीए के अनुसार भुगतान, कमीशन क्षमता के अनुपात में आनुपातिक आधार पर किया जा सकता है। आंशिक कमीशन क्षमता के क्रय का निर्णय पूरी तरह से खरीददार मध्यस्थ/खरीददार के पास है। यदि वे पूर्ण कमीशनिंग तक क्रय पर विचार नहीं करना चुनते हैं, तो आंशिक कमीशन क्षमता को एससीएसडी तक खुले बाजार में बेचा जा सकता है।

### 10 ऑफ-टेक बाधाओं के लिए मुआवजा

खरीददार को पारेषण बाधाओं और ग्रिड सुरक्षा के कारण विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा भंडारण क्षमता/निर्धारित विद्युत को ऑफ-टेक करने में बाध्यताएँ हो सकती हैं और ऐसे मामले में, कम ऑफ-टेक के लिए लागू मुआवजा निम्नानुसार होगा:

क. टोलिंग टैरिफ मॉडल पर खरीद के मामले में: कम ऑफ-टेक की अवधि विकासकर्ता को भुगतान के लिए उपलब्ध मानी जाएगी यदि वार्षिक उपलब्धता आरएफएस में निर्दिष्ट मानक वार्षिक उपलब्धता से कम है। इस तरह के समायोजन के बाद कुल उपलब्धता मानक उपलब्धता से अधिक नहीं होगी।

ख. समग्र टैरिफ मॉडल पर खरीद के मामले में: यदि वार्षिक आपूर्ति की गई ऊर्जा चयन के लिए अनुरोध (आरएफएस) में निर्दिष्ट अनुबंधित राशि से कम हो जाती है, तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

**भुगतान समायोजन:** - कम की गई ऊर्जा के लिए खरीददार आरएफएस में निर्धारित दर, जो कि विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) में समग्र टैरिफ के 60% से अधिक नहीं होगा, पर भुगतान करेगा।

### 13 चूक की घटना और उसके परिणाम

ख 'एम' के बराबर क्षति = 24 (चौबीस) माह

ग 'एम' के बराबर क्षति = 24 (चौबीस) माह

ड 'एम' के बराबर क्षति = 24 (चौबीस) माह

## परिशिष्ट-।

## पीएसपी के तकनीकी मापदंड, पीएसपी की विशेषता और कार्य निष्पादन मापदंड

- I. माध्यम 1 खरीद के लिए, खरीदार को आरएफएस के साथ परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें खरीदार द्वारा पहले से प्राप्त या आवेदन किए गए सहित अपेक्षित मंजूरी और अनुमोदन की स्थिति भी विनिर्दिष्ट की जाएगी। हालांकि, माध्यम 2 खरीद के लिए, निविदा में प्रासंगिक जानकारी विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
- II. पीएफआर के लिए एक अस्थायी प्रारूप नीचे दिया गया है। नीचे दी गई तालिका संपूर्ण नहीं है, और खरीदार आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकता है।
- III. पीएसपी के लिए सामान्य तकनीकी विवरण निम्नानुसार होंगे (केवल माध्यम-। के लिए लागू):

क्र.सं.	मापदंड	यूनिट
1	विद्युत संयंत्र का प्रकार (सतही/भूमिगत)	
2	पीएसपी का प्रकार	
3	संयंत्र की क्षमता	मेगावाट
4	भंडारण की अवधि	घंटे
5	उत्पादन चक्रों की संख्या (प्रति दिन)	
6	पंपिंग चक्रों की संख्या (प्रति दिन)	
7	इकाइयों की संख्या	
8	इकाई क्षमता (पंप/टरबाइन)	मेगावाट
9	अधिकतम हेड (टरबाइन)	मीटर
10	रेटेड हेड (टरबाइन)	मीटर
11	न्यूनतम हेड (टरबाइन)	मीटर
12	अधिकतम हेड (पंप)	मीटर
13	रेटेड हेड (पंप)	मीटर
14	न्यूनतम हेड (पंप)	मीटर
15	ऊपरी बांध की ऊंचाई और आयाम	मीटर
16	निचले बांध की ऊंचाई और आयाम	मीटर
17	अधिकतम हेड (निचला/ऊपरी)	मीटर
18	न्यूनतम हेड (निचला/ऊपरी)	मीटर
19	सक्षण हेड	मीटर
20	प्रस्तावित गति	आरपीएम
21	ऊपरी जलाशय क्षमता	एमसीएम
22	निचला जलाशय क्षमता	एमसीएम
23	लाइव भंडारण क्षमता (निचला/ऊपरी जलाशय)	एमसीएम
24	यूनिट डिस्चार्ज	क्यूबिक मीटर/सेकंड
25	जल कंडक्टर सिस्टम की लंबाई	मीटर
26	यूनिट की केंद्र रेखा	मीटर
27	नियोजित (प्लांड) यूनिट स्पेसिंग	मीटर

28	मशीन फ्लोर की नियोजित ऊंचाई	मीटर
29	जनरेटर बैरल व्यास	मीटर
30	पावरहाउस का नियोजित आकार (एल x डब्ल्यू x एच)	एमxएमxएम
31	ट्रांसफ़ॉर्मर कैर्वर्न हॉल का नियोजित आकार (एल x डब्ल्यू x एच)	एमxएमxएम
32	नियोजित स्विचयार्ड प्रकार (एआईएस/जीआईएस)	
33	किसी भी ईएण्डएम उपकरण के नियोजित अधिकतम संभावित परिवहन आयाम	एमxएमxएम
34	किसी भी ईएण्डएम उपकरण का नियोजित अधिकतम संभावित भार	किलोग्राम
35	स्विचयार्ड का नियोजित आकार (एलxडब्ल्यू)	एमxएम
36	पारेषण वोल्टेज	केवी
37	प्रस्तावित निकटतम पूलिंग स्टेशन	
38	पंपिंग ऊर्जा स्रोत का प्रस्तावित स्थान	

#### IV. पीएसपी मशीन की तकनीकी विशेषताएं और कार्यनिष्पादन

विशेषताएँ	आवश्यकताएँ
दक्षता	पंप टर्बाइन प्रभाव $>90.5\%$ मोटर जनरेटर प्रभाव $>98\%$
चक्र दक्षता*	$>75\%$ ;
ऑपरेटिंग मोड के बीच तेज़ संक्रमण	$\sim 7 - 15$ मिनट
पावर फैक्टर	
नियंत्रणीय प्रतिक्रियाशील शक्ति	हाँ
ग्रिड दोलन डैम्पिंग (पीएसएस)	हाँ
जड़ता	हाँ
टरबाइन पावर में तीव्र पारगमन (न्यून-फुललोड)/(फुल-न्यूनलोड)	$<60s$ . हाइड्रोलिक ट्रांजिएंट द्वारा सीमित
सिंक्रोनस कंडेनसर मोड	हाँ

\*खरीदार 80% से अधिक नहीं की उच्च दक्षता विनिर्दिष्ट कर सकता है।

#### V. कोड और मानक

- निर्माण और मशीन से संबंधित सामग्री और उपकरण, प्रासंगिक आईएस कोड और अंतर्राष्ट्रीय कोड के अनुरूप होंगे।
- सामग्री के लिए क्षेत्र और प्रयोगशाला परीक्षण और प्रक्रियाएं प्रासंगिक, आईएस कोड और अंतर्राष्ट्रीय कोड के अनुरूप होंगी।

#### VI. डिजाइन और सुरक्षा

- इन परियोजनाओं में नदी मोड कार्य, डिसिल्टिंग और सिल्ट फ्लशिंग की व्यवस्था, सर्ज चैंबर और बहुत छोटे जल कंडक्टर प्रणालियों की न्यूनतम आवश्यकता के साथ सरल डिजाइन होगा।
- परियोजना के स्थान पर न्यूनतम पर्यावरणीय मुद्दे होंगे जैसे कि मत्स्य पालन, पर्यावरणीय प्रवाह और आर एंड आर सहित सीएटी योजनाएँ।

**नोट:** बोली एजेंसी, सीईए या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी लागू दिशा-निर्देशों, मानकों आदि पर विचार करते हुए विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर इन विनिर्देशों को संशोधित कर सकती हैं।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता

**MINISTRY OF POWER**  
**RESOLUTION**

New Delhi, the 6th February, 2025

**TARIFF BASED COMPETITIVE BIDDING GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF STORAGE CAPACITY/ STORED ENERGY FROM PUMPED STORAGE PLANTS**

No. 42-26/1/2022-RCM-Part (3).—

**PART A: SCOPE**

**1. Background**

- 1.1.** The National Framework for Promotion of Energy Storage Systems (ESS) 2023 aims at facilitating India's Energy Transition and to enhance the energy security as the country shifts from fossil to non-fossil fuel sources, driven primarily by Renewable Energy (RE). As part of its action plan to combat Climate Change, India plans to have 500 GW of non-fossil fuel-based electricity installed capacity by 2030, so that the non-fossil and cleaner fuel-based sources comprise 50% of the installed capacity mix by 2030. However, the variability of RE—caused by factors such as Time of day, Weather conditions, Seasonal changes, and Geographic location—poses challenges to these goals. Renewable sources such as solar, wind, and run-of-the-river Hydro are not available on 24x7 basis. Energy Storage Systems (ESS) address this by storing excess energy and supplying it when needed, Improving Grid Stability, Enabling Peak Shifting, and Enhancing Renewable Energy integration.
- 1.2.** The National Electricity Plan 2023 foresees a need of approximately 74 GW/411 GWh of ESS by 2031-32, including 27 GW/175 GWh from Pumped Storage Plants (PSP) and 47 GW/236 GWh from Battery Energy Storage Systems (BESS).
- 1.3.** Usage of ESS provides benefits like reduced peak deficits, lower peak tariffs, carbon emissions reduction, and deferred capital expenditure on transmission and distribution. ESS also enables energy arbitrage, providing advantages for both the grid and consumers.
- 1.4.** The Guidelines for the procurement and utilization of Battery Energy Storage Systems (BESS) are already in place, but there are no separate guidelines for Pumped Storage Plants (PSP). Considering the distinct requirements of PSP in aspects such as land acquisition, permits and clearances, project timelines and performance parameters, separate guidelines for PSPs here-in are being formulated to address the specific nuances of PSP technologies.

**2. Objectives**

The following are the objectives of these Guidelines.

- 2.1.** To promote the development of Pumped Storage Plants (PSPs).
- 2.2.** To provide a transparent, fair, standardized procurement framework based on open competitive bidding with appropriate risk-sharing between various stakeholders.

**3. Applicability**

- 3.1.** These Guidelines are issued under Section 63 of the Electricity Act, 2003, for procurement of storage capacity/ stored energy from Pumped Storage Plants (PSPs) through competitive bidding.
- 3.2.** The provisions of these Guidelines shall be applicable on the following entities:
  - a.** Developers,
  - b.** Procurers (End Procurers or Intermediary Procurers)
- 3.3.** These Guidelines are applicable for the procurement of storage capacity or stored energy by the Procurers from existing, under-construction or new PSP projects.

**4. Definitions**

The terms used in these Guidelines will have the following meanings:

- a.** “Act” shall mean the Electricity Act, 2003, including subsequent amendments and clarifications issued thereof.

- b. “**Actual Commencement of Supply Date (ACSD)**” in relation to the contracted storage capacity shall mean the date corresponding to the actual date of commencement of storage capacity for pumping or generation of energy.
- c. “**Affiliate**” in relation to a Company shall mean an entity that controls, is controlled by, or is under the common control with, such Company. The expression ‘control’ shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.
- d. “**Annual Availability**” shall be as defined in the RfS.
- e. “**Appropriate Commission**” shall have the same meaning as defined in the Act.
- f. “**Appropriate Government**” shall have the same meaning as defined in the Act.
- g. “**Bidding Agency**” shall refer to the organization issuing the tender documents and carrying out the evaluation and selection process under these Guidelines.
- h. “**Bid Documents**” shall consist of RfS Document, PSPA and PSSA to be prepared by the Bidding Agency in line with these Guidelines.
- i. “**Composite Tariff Model**” shall mean a model in which the Procurer contracts for power or energy from storage-based system for a specified time. In either of these contracts, the energy for storage including losses in conversion is arranged by the Developer.
- j. “**Delivery Point**” shall mean any point as specified in the RfS Document where the PSP is delivering power.
- k. “**Effective Date of PPA**” shall mean the date of signing of PPA.
- l. “**End Procurer**” shall mean the final purchaser of storage capacity or stored energy from the Intermediary Procurer or the Pumped Storage Plant Developer, as the case may be, and shall include the distribution licensees.
- m. “**Financial Closure**” or “**Project Financing arrangements**” shall mean arrangement of necessary funds by the Developer towards 100% project cost either by way of commitment of funds by the Company from its internal resources (through a resolution passed by the Board of Directors) and/or tie up of funds through a bank/financial institution by way of sanction of a loan or firm commitment letter agreeing to finance.
- n. “**Infrastructure Sector**” means sectors notified by the Department of Economic Affairs in its Gazette Notification no. 13/1/2017-INF dated 14<sup>th</sup> November, 2017, and as amended from time to time.
- o. “**Intermediary Procurer**” shall mean an agency, including a trading licensee that acts as an intermediary between the End Procurer(s) and the Developer(s). This agency shall be responsible for aggregating storage capacity or stored energy purchased from different Developers, and subsequently selling it to the End Procurer(s). In cases where the trading licensee purchases storage capacity or stored energy from the Developer(s) and sells it to one or more distribution licensees, the trading licensee shall be deemed to be the Intermediary Procurer, and the distribution licensees shall be deemed to be the End Procurer(s) for the purpose of these Guidelines. So long as the Intermediary Procurer follows these Guidelines, the End Procurer(s) shall be deemed to have followed these Guidelines.
- p. “**Payment on Order Instrument**” shall mean a Letter of Undertaking (LOU) issued by an agency authorized by the Government of India or a State Government. This LOU shall guarantee to pay the Procurer (beneficiary) a specified amount in case of failure of the Developer to meet the obligations under the tender documents or contract. The LOU shall be issued on terms and conditions similar to that of a Bank Guarantee provided by any public sector bank.
- q. “**Procurer**” shall mean the End Procurer or an Intermediary Procurer, as the context may require.
- r. “**Pumped Storage Plants (PSPs)**” or “**Projects**” shall mean a hydro power plant, either on-stream or off-stream, that stores energy by pumping water from a lower stream/ reservoir to a upper reservoir and generates electricity by releasing it back through a turbine-generator.
- s. “**Pumped Storage Plant Developer (PSPD)**” or “**Developer**” shall mean an entity that owns or operates a PSP. The PSP can provide storage capacity or stored energy from various sources, under these guidelines.
- t. “**Pumped Storage Purchase Agreement**” or “**PSPA**” or “**Power Purchase Agreement**” or “**PPA**” shall mean an agreement between either the Intermediary Procurer or the End Procurer and the Developer outlining the terms for purchasing storage capacity or stored energy from the Pumped Storage Plant (PSP). The agreement can be based on a Tolling Tariff, Composite Tariff, or any other applicable model.
- u. “**Pumped Storage Sale Agreement**” or “**PSSA**” or “**Power Sale Agreement**” or “**PSA**” shall mean an agreement between the Intermediary Procurer and the End Procurer to facilitate the purchase of storage

capacity or stored energy under the Tolling Tariff or Composite Tariff or any other model. The PSA (or PSSA) contain the relevant terms from the corresponding Pumped Storage Purchase Agreement (PSPA) or Power Purchase Agreement (PPA) to enable a "back-to-back" contracting between the Developer and the End Procurer.

- v. **"Request for Selection"** or **"RfS"** or **"Tender"** or **"Bid Document"** shall mean the tender documents issued by the Bidding Agency, including Pumped Storage Purchase Agreement (PSPA) and Pumped Storage Sale Agreement (PSSA) as applicable, for procurement of storage capacity or stored energy through a competitive bidding process under these Guidelines.
- w. **"Scheduled Commencement of Supply Date (SCSD)"** in relation to the contracted storage capacity shall mean the date corresponding to the scheduled date of commencement of storage capacity for pumping or generation of energy as indicated in the RfS.
- x. **"Tolling Tariff Model"** shall mean a model in which the Procurer contracts the storage capacity. The energy for storage is provided by the Procurer and the same is off taken by the Procurer at a different time after accounting for losses.
- y. The term **"Contract"** in these Guidelines shall mean Pumped Storage Purchase Agreement or Power Purchase Agreement or Pumped Storage Sale Agreement or Power Sale Agreement.
- z. The term **"Supply"** in these Guidelines shall mean supply of stored energy or contracted PSP capacity.

## 5. Clarification and Modification to Guidelines

- 5.1. The Procurer shall seek prior approval of the Appropriate Commission for deviations from the process defined in the Guidelines before the initiation of the bidding process itself. However, for the purpose of clarity, if the Procurer while preparing the Bid Documents and other Project Agreements, provides detailed provisions that are consistent with these Guidelines, such detailing shall not be considered as deviations from these Guidelines.
- 5.2. In the event of any ambiguity, difficulty, or need for modification in interpreting or implementing these Guidelines, the Ministry of Power shall have the authority to provide clarification.

## 6. Applicable Laws and Regulations

- 6.1. All activities/ procurement being undertaken under these Guidelines will be subject to applicable laws, rules, orders, guidelines and regulations issued by the Appropriate Government and Regulatory Commissions.

# PART B: BID

## A. GENERAL CONDITIONS OF BID

### 1. BID/RFS Documentation

- 1.1. The Procurer shall prepare the bid documents in accordance with set Guidelines. The principles outlined in these Guidelines shall suitably be detailed in the Standard Bid Documents.
- 1.2. The Procurer shall invite the bidders to participate in the RfS prepared in accordance with these Guidelines. In case of bids initiated or already in progress before the notification of these Guidelines, the provisions outlined in the relevant tender or bid documents shall prevail.
- 1.3. The Bidding Agency will specify suitable technical and financial eligibility criteria for the bidders, in the tender documents.
- 1.4. The procurer may specify in the bid documents if the Project should be established at a site designated by the Procurer or at a site chosen by the Developer. If the Procurer does not specify the Project site in the bid documents, the Developer has liberty to choose its own site. Where the location/ site/ land is specified by the Procurer, the details thereof shall be indicated clearly in the bid documents.
- 1.5. The RfS shall outline the responsibilities of each party regarding the acquisition of necessary clearances, permits, licenses, land arrangements, etc, including the milestones related to land acquisition, connectivity, and other project requirements. The RfS shall specify the penalties for non-compliance with such milestones/requirements and the regular reporting requirements by the Developer.

### 2. Bid Process

- 2.1. The procurer shall call for the bids adopting a single stage, two part (Separate Technical Bid & Financial Bid), bidding process to be conducted preferably through electronic mode (e-bidding).

**2.2.** The technical bid shall be opened first and the financial bids of only those bidders who qualified in the technical bid evaluation stage, shall be opened. The Procurer may choose to conduct an e-reverse auction (e-RA) for selection of bidders, which shall be specifically mentioned in the notice inviting bids and the bid document. E-procurement platforms with a successful track record, adequate safety, security and confidentiality shall be used.

**2.3.** The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers and/or its own website and/or the Central/State Public Procurement Portal to accord wide publicity.

**2.4.** The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders and shall provide written interpretation of the tender documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision of the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be granted with a period of at least 7 days there from, for submission of bids.

### 3. Mode of Procurement

The mode of procurement shall be as specified in the **Special Conditions of Bid**.

### 4. Indicative Timelines for Bid Process

**4.1.** The indicative timelines for different activities of bid process shall be as specified in the **Special Conditions of Bid**.

**4.2.** The Procurer may specify different timelines as per the specific requirements in the RfS document. If the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before that event, or any other reason, such extension of time shall not in any way be construed as deviation from these Guidelines.

### 5. Bid Structure

**5.1.** **Bidding Parameter:** Allotment of contract shall be based on a Tariff Based Competitive Bidding process. The Bidding Agency may specify in the RfS, any of the bidding parameters specified in the **Special Conditions of Bid**, depending on the project specifics outlined in the RfS.

**5.2.** The Tariff shall be quoted at the **delivery point** to be specified in the RfS. In case of Composite Tariff Model, all the charges and losses till the Delivery Point shall be borne by the Developer, unless otherwise specified in the RfS. For the Tolling Tariff Model, the responsibility for the charges and losses till the Delivery Point shall be as specified in the RfS.

**5.3.** The minimum bid capacity of projects shall be as specified in the **Special Conditions of Bid**.

**5.4.** The Procurer may also define the maximum capacity to be allotted to a single bidder, considering factors like economies of scale, land availability, competition, and market development. The Procurer may allow the Developer to set up a higher capacity in projects developed in Mode-1 and in such case the Procurer shall have the first right of refusal to contract the additional capacity/energy.

### 5.5. Bid Responsiveness

The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions, inter-alia:

- Bidder or any of its Affiliate should not be a wilful defaulter to any lender;
- The Bidder and any of its Affiliate including any Consortium Member and any of its Affiliate, their directors should not have been barred by any government agency or an authority in India, or by the government of the jurisdiction of the Bidder or Members where they are incorporated or the jurisdiction of their principal place of business, or by any international financial institution such as the World Bank Group, Asian Development Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank etc. or by the United Nations or by any of its agencies as on the date of bid submission.

### 5.6. Eligibility and Qualification Criteria

- Formation of consortium by the bidders shall be permitted, in the case of, the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bid process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium.
- General Eligibility Criteria:** Bidders participating in the tenders issued under these Guidelines should fall under either of the following categories:

- i. A Company under the Companies Act, 2013.
- ii. A Foreign Company under the respective nation's laws.
- iii. Alternative Investment Funds (AIF) as registered under SEBI. "AIF" shall be as defined by SEBI.
- iv. A Consortium comprising of above entities.

The aforementioned categories would be subject to the relevant Acts, Rules, Guidelines, Orders and Policy documents of the Government of India, as amended from time to time.

c. **Technical Eligibility Criteria:** To encourage competition by way of increased participation and to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may specify additional Technical Eligibility Criteria as specified in the **Special Conditions of Bid**. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers - that are expected to meet the criteria - so that an adequate level of competition is achieved. The cut-off date for meeting the Technical Eligibility Criteria should generally be kept as the last date of bid submission.

d. **Financial Eligibility Criteria:**

i. **Net-worth/Assets under Management (AUM) or Investible Funds:**

- a. The Procurer shall specify that a Bidder must meet the net-worth requirement as specified in the **Special Conditions of Bid**.
- b. A Bidder who is a SEBI registered Alternative Investment Funds (AIF) must demonstrate a cumulative value of Assets under Management (AUM), as specified in the RfS. The net-worth of an AIF will be calculated as per the Companies Act, 2013 and the value of AUM will be calculated in accordance with the applicable SEBI (AIF) Regulations and certified by the AIF's Statutory Auditor.
- c. The net-worth of a Consortium Bidder shall be calculated as the combined net-worth of the Consortium members, along with the net-worth of Affiliates that undertake to contribute equity funding and provide Performance Guarantee (PG) if any of the Consortium member fails to meet the obligations as per the RfS.
- d. A Bidder (excluding AIF) can qualify based on the financial capability of their Affiliates. Further, in case of a Bidder who is part of a Bidding Consortium, any member can fulfil the criteria based on its Affiliate's financial capability. However, in both these cases, the Affiliates must commit to provide the required equity funding and Performance Guarantee (PG) if the Bidder fails to do so in accordance with the RfS document. Further, the affiliate(s) shall maintain their status of Affiliate (as per the definition mentioned in these Guidelines) informed in the bid, until the Actual Commencement of Supply Date (ACSD) of the project.

- ii. **Liquidity:** It is necessary that the Bidder has sufficient cash flow/internal accruals to manage the fund requirements for the Project. The Procurer may stipulate suitable parameters such as annual turnover, Profit Before Depreciation, Interest and Tax (PBDIT), internal resource generation, bidding capacity etc.

5.7. The quoted tariff shall be exclusive of GST. The developer will be obligated to undertake measures to reduce GST incidence by availing Input Tax Credit (ITC) or any other tax refund, exemption, or benefit under applicable tax laws. The final impact of GST shall be reimbursed by the Procurer on production of supporting documents adjusting for the benefits.

## 6. Technical Requirements

6.1. The Procurer shall specify the Technical Requirements in the Bid Documents as per the **Special Conditions of Bid**.

6.2. The Procurer will encourage the use of proven and operational technologies to reduce technology risks and ensure timely project commissioning. The specific technical standards applicable to the types of energy storage projects covered by these Guidelines will be outlined in the bidding documents. These standards will be regularly updated to align with the latest guidelines, notifications, and industry standards.

6.3. The technical Parameters of PSP, PSP Characterization and Performance Parameters are mentioned in **Appendix-I**.

## 7. Contractual Guarantees

7.1. The Developer shall provide the following instruments to the Procurer in terms of the RfS and the Contract.

## 7.2. Earnest Money Deposit (EMD)

- a. Procurer shall specify the quantum of the Earnest Money Deposit (EMD) as per the **Special Conditions of Bid**.
- b. The EMD for all the successful bidders shall be valid at least up to the Effective Date of PPA. Thereafter, EMD will be released and replaced by the Performance Guarantee (PG) in case of successful bidders. For the remaining bidders, the EMD shall be released after issuance of Letter of Award within the number of days specified in the **Special Conditions of Bid**.
- c. Forfeiture of EMD or debarring etc., as defined in these Guidelines, shall be undertaken in the event of failure of the successful bidder to execute the PPA within the stipulated time period.
- d. EMD shall be submitted in the form of
  - i. **Bank Guarantee**  
OR
  - ii. **Payment on Order instrument/Letter of Undertaking**  
OR
  - iii. **Insurance Surety Bonds** which would be paid unconditionally similar to a Bank Guarantee  
OR
  - iv. Any other approved instrument approved by Ministry of Finance, Government of India.

## 7.3. Performance Guarantee (PG)

- a. A Procurer will fix the Performance Guarantee (PG) as per the **Special Conditions of Bid**.
- b. A PG shall be submitted at the time of signing of the PPA in the form of:
  - i. **Bank Guarantee**  
OR
  - ii. **Payment on Order instrument / Letter of Undertaking** to be furnished by the bidders to be used to pay in case a Developer defaults in terms of PPA  
OR
  - iii. **Insurance Surety Bonds** which would be paid unconditionally similar to a Bank Guarantee  
OR
  - iv. Any other approved instrument approved by Ministry of Finance, Government of India.
- c. In addition to other remedies, this PG can be encashed to recover any damages/dues of the Developer in terms of the PPA. The damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PG, upon the default of the Developer under the PPA, shall be credited to the Procurer.
- d. The PG will be returned, after deducting any liquidated damages, to the Developer within '**D**' days of the Actual Commencement of Supply Date (ACSD) of the full contracted capacity or the last part of contracted capacity accepted by the Procurer. However, the Procurer/Intermediary Procurer may extend this period up to a maximum of '**M**' months from the ACSD, which will be clearly specified in the Bidding Documents. '**D**' and '**M**' are specified in the **Special Conditions of Bid**. In the case of partial commissioning of the contracted capacity, the PG corresponding to the part commissioned contracted capacity shall be released after deducting any liquidated damages, within the time specified in the Bidding Documents.
- e. As an alternative to encashing the PG, the Procurer/Intermediary Procurer may allow the Developer to furnish the requisite amount through Demand Draft/electronic payment against the release of the relevant PG without any encashment.
- f. A Procurer may release the Bank Guarantee submitted by the Developer if the Developer is able to replace the same with an alternative PG as per these Guidelines, issued by any agency notified by the Government of India or State Government, to pay in case a Developer defaults in terms of PPA.
- g. **Compliance of FDI Laws by foreign bidders:** In case, a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.

## 8. Submission and Evaluation of Bids

- 8.1. The bidders may be required to submit non-refundable processing fee and/or success fee, as specified in the RfS.
- 8.2. The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an EMD along with the bids.
- 8.3. The Procurer shall constitute a committee for evaluation of the bids called Evaluation Committee, with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters/ bid evaluation. The evaluation committee should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the requirement. The evaluation committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned with the prevailing market prices.
- 8.4. The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS shall be considered for further evaluation on the price bids.
- 8.5. To ensure competitiveness, the minimum number of qualified Bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.
- 8.6. The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the bid conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at this stage.
- 8.7. Bid Evaluation shall be carried out in terms of parameters as mentioned in the RfS through ranking of Bids in ascending order of the Bidding Parameter. The Bidding Agency may carry out electronic reverse auction for award of Projects.
- 8.8. The detailed procedure for evaluation of the bid and selection of the successful bidder(s) shall be provided in the RfS.
- 8.9. After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity with the provisions of these Guidelines.

## B. SPECIAL CONDITIONS OF BID

*The clauses in the Special Conditions correspond to and must be read in conjunction with the clauses in the General Conditions within the respective part of the document.*

### 3. Mode of Procurement

The mode of procurement may be either of the following:

- a. **Mode 1 - Procurement from a PSP developed on a site identified by the Procurer:** The Procurer may choose to locate the Project at a site pre-specified and identified in the bidding documents. Where the site belongs to the Government or a Government entity, to ensure inter-generational equity in the utilisation of such site, the development shall be on “Build Own Operate Transfer (BOOT)” basis for a period of 25 to 40 years, which shall be specified in the RfS. In BOOT mode of implementation, the project will be transferred after the end of term of the agreement to an entity identified by the State Government at a pre specified amount to be specified in the RfS.

The Procurer shall issue a Detailed Project Report (DPR) made in accordance with the provisions of the relevant Guidelines along with the bid.

Further, to de-risk the project, the procurer shall form a Special Vehicle (SPV) which shall undertake all pre-feasibility activities. These activities include applying for and initiating the process of securing all clearances including environmental clearance, forest clearance, land procurement, and other statutory clearances as may be applicable. The SPV shall be incorporated as a wholly owned subsidiary of the procurer entity with a minimum shareholding of Rs. 1 lakh under the Companies Act. The SPV incorporated by the procurer would be transferred to the successful bidder at a cost equivalent to the sum total of the par value of shareholding in the company and the expenditure incurred by the procurer in operation of SPV, which shall be pre-specified in the RfS.

**b. Mode 2 - Procurement from a PSP developed on a site identified by the Bidder or an already commissioned PSP or under development PSP:** In this case Supply will be from a PSP developed on a site identified by the bidder or from an already commissioned or under development PSP. In this case the development may be on “Build-Own-Operate (BOO)” basis for a period of 15 to 40 years, which shall be specified in the RfS. PSP Developers may self-identify potential sites where a PSP can be constructed or offer storage from already commissioned or under development projects. The PSP Developer shall obtain the statutory clearances including concurrence under Section 8 of the Electricity Act, environmental clearance, forest clearance, land procurement etc. before the commencement of construction of the project. The Procurer shall not be responsible in case of delay in obtaining any required clearances. The selected bidder (s) may be required to submit the approved DPR before signing the PPA.

#### 4.1. Indicative Timelines

a. The indicative timeline for different activities under the **Mode 1 and Mode 2** shall be as under:

Sl. No	Event	Time from Zero date (for Mode 1 of procurement)	Time from Zero date (for Mode 2 of procurement)
1	Date of issue of Bid Documents	Zero date	Zero date
2	Pre-bid conference, Bid Clarifications, opening of online Data Room to share project specific details including site, if specified by the Procurer etc., and revision of RfS document	**	**
3	Bid submission	90 days	60 days
4	Evaluation of Technical bids	120 days	90 days
5	Evaluation of Financial bids and conduct of e-RA	150 days	120 days
6	Issuance of Letter of Award	195 days	165 days
7	Date of filing of petition for adoption of tariff by SERC/CERC <sup>#</sup>	225 days	195 days
8	a. Signing of Share purchase agreement of SPV (Mode-1) (if applicable) and/or b. Signing of PPA and PSA (if applicable)	285 days	255 days

\*\* In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders with additional time.

# Commission shall adopt tariff within 60 days of filing the petition.

#### 5.1 Bidding Parameters:

- a. Storage charge (Rs/{MW/kW}/{year/month})
- b. Storage charge (Rs/{MW/kW}/{year/month}) with a pre-specified VGF/ Annuity support
- c. Composite Tariff (Rs/kWh basis) for electricity including the cost of input power and storage. In this case input power is arranged by the Developer (“Composite Tariff Model”)

Note:

1. In case the procurement is based on storage charge i.e., “**Tolling Tariff Model**”, the input power shall be arranged by the Procurer of the storage capacity.
2. The Procurer may specify an escalating tariff structure for the Bid Parameters specified in 5.1(a), (b) and (c) in the Bid document.

**5.3 Minimum Bid Capacity:** For ISTS connected projects, the minimum bid capacity that can be offered by the bidder should be 50 MW. For InSTS connected projects, i.e., when the Procurer and the identified PSP are within the same State, the minimum bid capacity may be at least 10 MW. For projects in North-Eastern States, Special Category States, and other InSTS-connected projects, based on the availability of land and transmission facilities, a smaller minimum capacity may be allowed but this should be clearly specified beforehand in the RfS. However, the Procurer may specify a project size different from the limits specified hereunder in the RfS document.

## 5.6 Qualification requirements to be met by the bidders

- a.** Technical Eligibility Criteria: Applicants must demonstrate experience in developing infrastructure sector projects within the past five (5) years. Specific details will be outlined in the Request for Proposal (RfS), including:
  - Minimum Aggregate Capital Expenditure: The total capital expenditure for all qualifying infrastructure projects undertaken in the last five (5) years must meet a threshold specified in the RfS.
  - Minimum Capital Expenditure per Project: Each qualifying infrastructure project must have a minimum capital expenditure as defined in the RfS.
- b.** Financial Eligibility Criteria:
  - ii. *Net-worth/Assets under Management (AUM) or Investible Funds: Net-worth equivalent of at least 20% of the estimated capital cost of the contracted capacity of the PSP for the financial year in which bids are issued. The estimated capital cost will be determined by the Bidding Agency.*

## 6.1 Technical Requirements in Bid Documents

- a.** The procurer shall specify the following while defining the technical requirements for PSP:
  - i.** Power capacity in MW
  - ii.** Energy capacity in MWh
  - iii.** Pumping/ Generation duration in hours per day (Maximum number of Continuous and Non-Continuous hours in a day)
  - iv.** Usage in cycles per day/month/quarter/year/entire contract period as applicable.
- b.** The Procurer may choose to specify additional performance parameters also for bid evaluation as per its requirement:
  - i.** Availability (%)
  - ii.** Switchover time between generation and pumping mode and vice versa.
  - iii.** Cycle Losses, if applicable
  - iv.** Other performance parameters

The performance parameters will be evaluated based on operational data, considering either the entire project or the contracted capacity, as applicable.

## 7.2 Earnest Money Deposit (EMD)

- a** EMD shall not be less than **2% (two percent)** of the estimated capital cost of the contracted capacity in MW for the new PSP for the year in which bids are invited or as per the upper limit stipulated by Ministry of Finance from time to time, whichever is lower.
- b** EMD shall be released within 15 days of issue of LOA for other than selected bidder.

## 7.3 Performance Guarantee (PG)

- a** PG shall not be less than **5% (five percent)** of the estimated capital cost of the contracted capacity in MW for the new PSP for the year in which bids are invited, or as per the upper limit stipulated by Ministry of Finance from time to time, whichever is lower.
- d** **Timeline 'D'** = Sixty (60) days, '**M**' = Six (6) months

## PART C: CONTRACT

### A. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

#### 1. Contract Award and Conclusion

- 1.1.** The PPA shall be signed by the Procurer with the successful Bidder/ Project Company or the SPV as the case may be.

- 1.2. In case of involvement of an Intermediary Procurer, the Intermediary Procurer shall enter into a PPA with the Developer(s) and a PSA with the End Procurer (s). The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA to enable back-to-back contracting of stored energy/storage capacity between the Developer and the Procurer. The PPA(s) should preferably be signed immediately after signing of the PSA(s). The Intermediary Procurer shall be entitled to charge a trading margin at 7 paise per unit of discharged energy or as specified by the Appropriate Commission, for composite tariff model and 1% of the capacity charges in ( Rs/MW/month) or as specified by the Appropriate Commission, for Tolling tariff model, from the Procurer for purchase and sale of storage capacity or stored energy.
- 1.3. The power procurement for Distribution licensees in some States is centralized through a holding company or a government agency. Such companies/ agencies will be considered as Procurer and not as Intermediary Procurer for the purposes of these Guidelines.
- 1.4. In case of delay in signing of PPA beyond a period of six (6) months from the date of issuance of LoAs, or any other extended date as mutually agreed between the Bidding Agency and the successful bidders not exceeding 12 months, the awarded capacity shall stand cancelled. In certain cases, after the above deadline, if the cumulative capacity eligible for signing of PPAs is lower than the cumulative capacity awarded under the tender, further course of action to be decided by the Bidding Agency will be clearly specified in the Bid document.
- 1.5. To ensure transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff/ charges quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least thirty (30) days.
- 1.6. The Procurer or the Intermediary Procurer shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariff under section 63 of the Act within thirty (30) days of issue of LoA.
- 1.7. The tariff shall be adopted by the Appropriate Commission within sixty (60) days of the application date. If the Appropriate Commission fails to decide within sixty (60) days of the application date, the Procurer(s) shall grant an extension of time in Scheduled Commencement of Supply Date (SCSD) and Financial Closure (FC) Date to the Developer. This extension should correspond to the time taken by the Appropriate Commission in adoption of tariff beyond sixty (60) days of application date.
- 1.8. The PPA shall include standard provisions, including but not limited to the following, which, unless otherwise specified, will be mirrored in the PSA.

## 2. Term

The term of the PPA will be determined by the Procurer based on the intended use of the plant, and this will be explicitly specified in the RfS document. Following the expiry of the PPA period, the Developer will be free to continue operating the Project. It is important to note that when the Project site is designated by the Procurer, the Procurer's responsibility for land arrangements shall be limited to the PPA period.

## 3. Performance Parameters

Performance parameters and other conditions shall be as specified in the **Special Conditions of Contract**

## 4. Liquidated Damages

- 4.1. The Liquidated Damages on account of shortfall in meeting performance criteria, specified in the Bidding Documents, PPA, or PSA, should be genuine and a reasonable estimate of potential damages for the Procurer/ Intermediary Procurer(s).
- 4.2. Any shortfall in availability of capacity below the committed capacity shall incur charges on a pro-rata basis at the capacity rate or at a predetermined number specified in the RfS.
- 4.3. Predefined Liquidated Damages for deviations related to ancillary services parameters, as specified in the RfS, will be imposed.
- 4.4. Any other Liquidated Damages specified in the **Special Conditions of Contract** and RfS Document.

## 5. Terms of procurement

- 5.1. The penalty for non-performance shall be as specified in the RfS. The scheduling and its punching thereof at different Regional Load Despatch Centres (RLDCs) / State Load Despatch Centres (SLDCs) (including the injecting, intervening and buyer SLDCs / RLDCs) shall be the responsibility of Developer.
- 5.2. Additional terms will be as specified in the **Special Conditions of Contract**

## 6. Deviation Settlement Mechanism (DSM)

For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. The DSM charges at the Project end shall be settled by the Developer.

## 7. Financial Closure (FC)

The following provisions shall be applicable only in case of new Projects to be commissioned by the Developers.

- a. The Developer must achieve Financial Closure (FC) within the period specified in the **Special Conditions of Contract** from the Effective Date of PPA. However, if there is a need to modify this period for any reason, the Procurer has the authority to do so.
- b. In case of a delay in achieving Financial Closure, the Procurer/ Intermediary Procurer will encash the PG, unless the delay is due to allotment of land by the Government, delay caused by Government (not attributed to the Developer), or due to Force Majeure. The Procurer may consider an extension for Financial Closure upon the Developer's request, subject to payment of extension charges specified in the **Special Conditions of Contract**. This extension will not affect the SCSD. Any extension charges paid will be refunded without interest upon successful commissioning within the SCSD. Any non-refunded penalties or extension charges shall go to the Procurer.

## 8. Transmission Connectivity

- 8.1. The responsibility of obtaining Transmission Connectivity to ISTS network under GNA regulation or to the InSTS network will lie with the Developer and shall be at the cost of Developer.
- 8.2. The Developer within '**D**' days of issuance of the LoA shall apply for Connectivity/GNA/Open Access to the CTU/STU Grid (as required) for technical feasibility of Connectivity/Open Access of the plant to InSTS/ISTS substation. The value of '**D**' is specified in the **Special Conditions of Contract**.
- 8.3. The End Procurer shall be liable for Inter-state/ Intra-State transmission charges and losses beyond the Delivery Point under the Applicable Laws. Inter-State/ Intra-State Transmission Charges and losses up to the Delivery Point shall be borne by the Developer.
- 8.4. The energy supplied to the Procurer shall be measured at the Metering Point or any additional point(s) as specified in the Bidding Document. The Metering Point shall be the low voltage bus bar of the InSTS/ ISTS substation at which power is injected in the transmission system of STU/CTU.
- 8.5. Unless otherwise provided, the transmission of power up to the point of interconnection where metering is done for energy accounting shall be the responsibility of Developer and at its own cost. Additional conditions shall be as specified in the **Special Conditions of Contract**.

## 9. Commencement of Supply

- 9.1. The PPA between the Developer and Procurer/Intermediary procurer shall clearly indicate the SCSD and quantum of capacity.
- 9.2. The projects shall generally commence services, within a period specified in the **Special Conditions of Contract**. However, if for some reason, the SCSD period needs to be kept longer/ shorter than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.
- 9.3. **Early Commencement.** The Developer shall be permitted commencement of Supply corresponding to full as well as part contracted capacity, even prior to the SCSD. The Developer shall give at least '**D**' days (as specified in the **Special Conditions of Contract**) advance notice to both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer regarding the advance commissioning of full or part contracted capacity. The End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall give acceptance for availing such storage capacity or stored energy within '**D**' days from the date of service of notice. In case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer do not give their acceptance within the stipulated period, the developer can sell the stored energy/storage capacity to the extent not accepted by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer in the power exchanges or through bilateral arrangements. In case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer give their acceptance, the End Procurer(s) will be accorded priority in availing the Supply.
- 9.4. **Part Commencement of Supply.** In case of part commencement of the contracted capacity, the minimum capacity for the acceptance shall be as specified in **Special Conditions of Contract**. However, penalties, as per the PPA, may apply to the non-commissioned part. Despite part or full commencement dates, the SCSD remains unchanged. The PPA remains in force for the entire term, starting from the SCSD.

**9.5. Early and Part Commencement of Supply.** In case of early and part commencement, the tariff payable by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall be equal to the PPA tariff. Other conditions for early and part commencement shall be as specified in **Special Conditions of Contract**.

**9.6. Delay in Commencement of Supply** beyond the SCSD shall involve penalties on the Developer, as detailed below:

- a. For Delay in Commencement of Supply up to 6 (six) months from SCSD, encashment of Performance Guarantee (PG), on per day basis and proportionate to the contracted capacity that has not commenced Supply.
- b. For Delay in Commencement of Supply beyond six months from SCSD, the contracted storage capacity shall stand reduced to the project capacity that has commenced Supply within the period of SCSD plus 6 (six) months. The PPA for the balance contracted capacity that has not commenced Supply shall stand terminated.

**9.7. Delay in Commencement of Supply on account of delay in Connectivity/Grid Access Operationalisation**

Delays in granting or operationalizing Grid Access by CTU/STU, or in the readiness of the ISTS/InSTS substation at the Delivery Point/Injection Point, including the power evacuation and transmission infrastructure of the ISTS/InSTS network until the SCSD, are considered as delays beyond the Developer's control, if the following conditions are met:

- a. The Developer has completed all application formalities as per the Connectivity Procedure.
- b. The Developer has adhered to the relevant procedure notified by the Appropriate Commission/CTU/STU.
- c. The delay is caused by STU/CTU/transmission licensee and is beyond the Developer's control.

The SCSD for such projects will be adjusted to a date thirty (30) days after the readiness of the Delivery Point and power evacuation infrastructure and/or the operationalization of the Grid Access. The decision regarding the necessary extension due to the above-mentioned factors will be made by the Procurer/Intermediary Procurer.

## 10. Compensation for Offtake Constraints

Compensation for Offtake Constraints due to transmission unavailability and grid security shall be as specified in the **Special Conditions of Contract**.

## 11. Payment Security Mechanism

- 11.1.** In case the End Procurers are Distribution Licensees where the tariff is determined or adopted by the Appropriate Commission, adequate payment security shall be provided as per Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022 including amendments and clarifications issued from time to time.
- 11.2.** If the Supply is meant for sale through power markets, the shortfall/surplus in revenue shall be treated as per the relevant Guidelines/orders issued by the Central Government and regulated by the Central Commission.

## 12. Force Majeure

- 12.1.** The PPA shall contain provisions with regard to force majeure definitions, exclusions, applicability, and available relief on account of force majeure, as per the industry standards.
- 12.2.** The Developer shall intimate the Procurer about the occurrence of force majeure within 15 (fifteen) days of the start of the force majeure and the Procurer shall respond on his claim within 15 days of the receipt of the intimation.

## 13. Event of Default and Consequences Thereof

While detailed provisions with regard to the event of default of the concerned parties and its resulting consequences shall be given in the PPA/PSA, the broad principles of contractually dealing with the default of the Developer and the Procurers (excluding the Intermediary Procurer) shall be as follows.

- a.** For delay in commencement of Supply beyond SCSD, the Developer event of default shall have been construed to have occurred and consequences shall be in accordance with these Guidelines.

- b.** In the event the Developer fails to maintain the minimum performance requirement continuously for a period specified in the RfS, the Developer shall be in default and the PPA shall be liable to be terminated. Further, the Developer shall be liable to pay to the Procurer, damages, equivalent to '**M**' months (as specified in **Special Conditions of Contract**), or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity.
- c.** In the event the Developer assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure period, as may be provided in the PPA, the Developer shall pay to the Procurer, damages, equivalent to '**M**' months (as specified in **Special Conditions of Contract**), or balance PPA period whichever is less, of tariff for its contracted capacity. The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of Performance Guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.
- d.** In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Developer, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution provisions provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Developer within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA.
- e.** If the Procurer/Intermediary procurer is in default on account of reasons including *inter alia* failure in timely payment of the dues, in accordance with the RfS or repudiation of the PPA, the Developer may terminate the PPA at its discretion. The defaulting Procurer shall pay to the Developer, damages, equivalent to '**M**' months (as specified in the **Special Conditions of Contract**), or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity.
- f.** If the Developer agrees to Supply all or part of the Contracted Capacity of the Procurer from an alternate source during the period between the SCSD and ACSD, and on the terms specified in the PPA, the Damages payable under this Clause will be proportionally reduced based on the extent of such Supply vis-à-vis the Contracted Capacity. If the Project is not completed and the ACSD does not occur within 180 days from the SCSD, and unless the delay is on account of Force Majeure or attributable to the Procurer, the Procurer may terminate the PPA at its discretion.

#### 14. Change in Law

The provisions for Change in law shall be specified in the RfS and PPA, in accordance with the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021. Further, the term Change in Law ("CIL") shall refer to the occurrence of any event related to the project from seven (7) days prior to the last date of Bid Submission.

#### 15. Minimum Paid-up Share Capital/ Shareholding to be held by the Promoter

- 15.1.** The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/ project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one percent) at any time prior to the ACSD. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/ project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to the ACSD. Further, in case the Project is executed by the successful bidder itself, it shall ensure that the controlling shareholding of the bidding company/consortium remains unchanged until the ACSD. The successful bidder shall provide the information about its shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.
- 15.2.** Any change in the shareholding after the ACSD can be undertaken under intimation to the Procurer.
- 15.3.** In the event, the Developer is in default to the lender(s), the lenders shall be entitled to undertake "Substitution of Promoter" in consultation with the Procurers.

#### 16. Construction and Performance Monitoring

- 16.1.** All grid-connected projects, covered under these Guidelines, must install necessary equipment to continuously record the Project's performance. The Developer shall be required to submit this data to Authorities/Agencies as specified in the RfS Document in online/electronic mode for the entire duration of PPA. In this regard, they shall also mandatorily grant access to the Procurer and Ministry of Power/ Central Electricity Authority or any other agency designated by Appropriate Government, to the remote monitoring portal of the power plants on a 24×7 basis. Geo-tagging of the Projects shall be mandatory.
- 16.2.** When a Project Site is identified by the Developer then the Developer shall be responsible for obtaining all the clearances and the Procurer shall not be responsible for delay in obtaining such clearances. The Developer should ensure that various preparatory and implementation activities are completed as per the timelines stipulated in the RfS to ensure timely commencement of Supply.

## 17. Role of State Nodal Agencies and Other Facilitators

The State Nodal Agencies appointed by respective State Governments will provide necessary support to facilitate the required approvals and sanctions in a time bound manner to achieve commissioning of the Projects within the scheduled timeline. This may include facilitation in the following areas:

- a. Co-ordination among various State and Central agencies for speedy implementation of Projects.
- b. Support during commissioning of Projects.

## 18. Dispute Resolution Mechanism

- 18.1. Any dispute related to tariff or the matters dealt under provisions of Section 79 and Section 86 of the Electricity Act, 2003 shall be adjudicated by the Appropriate Commission. All other disputes shall be resolved by the Dispute Resolution Committee set up by the Appropriate Government and if the Committee fails to resolve the dispute, it shall be resolved through arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996.
- 18.2. The Dispute Resolution Committee will be an additional forum beyond the provisions of the law and can be used by the relevant parties at their option.

## B. SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT

*The clauses in the Special Conditions correspond to and must be read in conjunction with the clauses in the General Conditions within the respective part of the document.*

### 3. Performance Parameters

- a. The performance parameters of the Project specified in the bidding documents, which may include availability, charging/discharging rate, efficiency, ramp rate, cycling losses, capacity degradation, and daily/monthly cycles, shall be clearly articulated in the PPA. Where availability is a performance criterion, the PPA should specify the minimum level at which the Developer must maintain the PSP Capacity. Depending on the PSP's intended usage, the Developer may need to meet monthly and/or annual availability requirements or declare availability on a day-ahead basis. The Procurer may specify specific hours and performance parameters, restricting the minimum availability criteria to specified hours or peak hours, with any shortfalls calculated accordingly.
- b. When the contract is for storage, the energy shall be procured independently by the End Procurer and stored in the provided capacity. The Developer will return the stored energy, accounting for predetermined conversion losses. The End Procurer is obligated to pay the storage charge for the provided capacity, whether or not the capacity is fully utilized.

### 4.4. Additional Liquidated damages for performance shortfalls

The Developer shall bear the cost of energy loss exceeding the guaranteed parameter (specified in the RfS Document) at the tariff of input energy provided by the procurer or any number specified in the RfS.

### 5.2 Additional Terms of Procurement

- a. For any deficiency in available capacity/energy, the PPA shall have appropriate provisions for liquidated damages. The amount of such penalty will be equal to one and a half times of the PPA tariff for the shortfall in storage capacity/ energy, in accordance with the terms of the PPA.
- b. In case, the availability of energy is more than the maximum specified annual contracted stored energy, the Developer will be free to sell it to any other entity without providing the first right of refusal to the Procurer(s).
- c. The Developer may also sell un-requisitioned capacity/energy to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer(s).

### 7. Financial Closure

- a. Financial Closure period will be within **12 months**.

**b.** Extension charges will be **Rs. 1,000 per MW** of contracted capacity per day of delay in SCSD.

**8. Transmission Connectivity**

**8.2** Connectivity/GNA/Open Access to the CTU/STU Grid to be applied with ‘D’ = Sixty (60) days of issue of LoA.

**8.5. Transmission Connectivity additional conditions**

In case of procurement of storage capacity, the responsibility of supplying charging energy to the contracted PSP capacity at the Metering Point as well as transmission of discharged energy from contracted PSP capacity beyond the Metering Point shall be that of the End Procurer.

**9. Commencement of Supply**

**9.2 Commencement of Storage Schedule**

(i) Projects shall generally commence within a period of:

Sl. No.	Procurement Mode Type	Type of PSP	SCSD (Months) after Effective Date of PPA
1.	Mode 1	Off-river	48 months
		On-river	66 months
2.	Mode 2	-	As per the requirement of procurer

**9.3 Early Commencement**

Notice period will be at least ‘D’ = Fifteen (15) days

**9.4 Minimum part capacity for commissioning**

The minimum capacity of first part for part commissioning shall be 50% of Project Capacity or 50 MW, whichever is lower.

**9.5. Early and Part Commissioning**

In capacity procurement contracts, if the project is partially commissioned, payments according to the PPA may be made on pro-rata basis, proportionate to the commissioned capacity. The decision to procure the part-commissioned capacity lies solely with the Procurer/Intermediary Procurer. If they choose not to consider procurement until full commissioning, the part-commissioned capacity can be sold in the open market until the SCSD.

**10. Compensation for off-take constraints**

The Procurer may be constrained to off-take the energy storage capacity offered/ power scheduled by the Developer on account of transmission constraints and grid security and in such case, the applicable Compensation for reduced off-take shall be as under:

**a. In case of procurement being on Tolling Tariff Model:** Period of reduced off-take to be considered as deemed available for payment to Developer if the annual availability is less than normative annual availability specified in RfS. The total availability after such adjustment shall not be higher than normative availability.

**b. In case of procurement being on Composite Tariff Model:** If the annual energy supplied falls below the contracted amount specified in the Request for Selection (RfS), the following provision shall apply:

(i). **Payment Adjustment:** - The Procurer for the reduced energy will pay at a rate stipulated in the RfS but not exceeding 60% of the composite tariff in the Power Purchase Agreement (PPA).

**13. Event of Default and Consequences Thereof**

**b** Damages equivalent to ‘M’ = 24 (Twenty-Four) months

**c** Damages equivalent to ‘M’ = 24 (Twenty-Four) months

**e** Damages equivalent to ‘M’ = 24 (Twenty-Four) months

### Technical Parameters of PSP, PSP Characterization and Performance Parameters

**I.** For **Mode 1 Procurement**, the Procurer shall submit the Pre-Feasibility Report (PFR) and Detailed Project Report (DPR) of the project along with the RfS, which shall also specify the status of requisite clearances and approvals, including those already obtained or applied for by the Procurer. However, for **Mode 2 Procurement**, relevant information may be specified in the tender.

**II.** A tentative format for the PFR is provided below. The table below is not exhaustive, and the Procurer may add additional information as needed.

**III. General Technical particulars for PSP shall be as under (applicable for Mode-I only):**

S. No.	Parameter	Unit
1	Type of Power plant (Underground/Surface)	
2	Type of PSP	
3	Capacity of the plant	MW
4	Duration of storage	Hours
5	Number of Generation Cycles (per Day)	
6	Number of Pumping Cycles (per Day)	
7	Number of units	
8	Unit Capacity (Turbine/Pump)	MW
9	Maximum Head (Turbine)	Meter
10	Rated Head (Turbine)	Meter
11	Minimum Head (Turbine)	Meter
12	Maximum Head (Pump)	Meter
13	Rated Head (Pump)	Meter
14	Minimum Head (Pump)	Meter
15	Elevation & dimensions of upper dam	Meter
16	Elevation & dimensions of lower dam	Meter
17	Maximum head(upper/lower)	Meter
18	Minimum head (upper/lower)	Meter
19	Suction Head	Meter
20	Proposed Speed	RPM
21	Upper reservoir capacity	MCM
22	Lower reservoir capacity	MCM
23	Live storage capacity (Upper/Lower Reservoir)	MCM
24	Unit Discharge	Cubic Meter/ Second
25	Length of water conductor system	Meter
26	Centre line of unit	Meter
27	Planned Unit spacing	Meter
28	Planned Elevation of machine floor	Meter
29	Generator barrel diameter	Meter
30	Planned Size of powerhouse (L X W X H)	MxMxM
31	Planned Size of Transformer Cavern/Hall (L X W X H)	MxMxM
32	Planned Switchyard Type (AIS/GIS)	
33	Planned Maximum possible transportation dimensions of any E&M equipment	MxMxM
34	Planned Max possible weight of any E&M equipment	Kg
35	Planned Size of Switchyard (L X W)	MxM
36	Transmission Voltage	kV
37	Proposed Nearest Pooling Station	
38	Proposed Location/Locations of Pumping Energy Source	

**IV. Technical features and performance of PSP Machine**

Features	Requirements
Efficiency	Pump Turbine eff. >90.5% Motor Generator eff. >98%
Cycle efficiency*	>75%

Fast transition between operating modes	~7 - 15 min
Power factor	
Controllable reactive power	Yes
Grid oscillation damping (PSS)	Yes
Inertia	Yes
Fast transition in turbine power (min.-Full load) / (Full – min. load)	<60s. Limited by hydraulic transient.
Synchronous Condenser Mode	Yes

*\*Procurer may specify any higher efficiency not exceeding 80%.*

#### V. Codes & Standards

1. Material and equipment pertaining to construction and machine shall conform to relevant IS codes and international codes.
2. Field and laboratory testing, and procedures for material shall conform to relevant IS codes and international codes.

#### VI. Design & Safety

1. These projects shall have simpler design with minimum requirement of River Diversion works, Desilting & Silt Flushing arrangements, Surge Chambers and very small water conductor systems.
2. Location of project shall have minimal environmental issues such as, Fisheries, Environmental Flows and CAT Plans including R&R.

*Note: Bidding Agency may modify these specifications based on specific requirements considering applicable Guidelines, Standards, etc. issued by CEA or any other Govt. Agency.*

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer